Central Universities Amendment Bill, 2023

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 10, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023.

श्री राजीव प्रताप रूडी जी ।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति जी, मैं कल बोल रहा था, उस समय मुझे बोलने का पूरा समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं आपसे उसे पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ।

सभापति महोदय, मैं कल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल पर बात कर रहा था, जो तेलंगाना के लिए बनाया जाना है। मुझे लगा कि अगर अध्ययन करके शिक्षा के जगत में बोलना है तो हम देखें अक्तूबर 2014, 2015, 2016, 2018 और 2023 में माननीय प्रधान मंत्री जी का एम्स में कन्वोकेशन एड्रेस था। जम्मू में शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी में एड्रेस था, पीजीआई के मेडिकल कॉलेज में एड्रेस था। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी सिंधिया स्कूल में गए थे, वहां पर एड्रेस था। वर्ष 2016 में कटरा में कन्वोकेशन एड्रेस था तथा माननीय प्रधान मंत्री जी आईआईटी मुम्बई में भी गए थे, वहां पर भी कन्वोकेशन एड्रेस था।

मुझे लगता है कि उन सभी विषयों को पढ़ लिया जाए, तो शिक्षा जगत की सोच की क्या प्रणाली होनी चाहिए, पूरे स्पष्टता के साथ प्रधान मंत्री जी ने इन कनवोकेशंस में कहा है। मैं वहीं से प्रेरणा लेकर बात आगे बढ़ाऊंगा।

जब कल मैं अपनी बात समाप्त कर रहा था, तो सभापति महोदय मैंने कहा था, आखिर में, मैंने बिहार के बारे में चर्चा संदर्भित करते हुए बताया था कि वहां सेशन लेट है और आज अधिकांश बच्चे कोचिंग-इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। आज साढ़े सात लाख से अधिक बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, जो खचाखच भरे हुए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खाली हैं। अगर डिग्री की बाध्यता न हो, तो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से ही परीक्षा देकर पास कर जाएं, लेकिन बाध्यता के कारण यह नहीं होता है। हमारे यहां एग्जामिनेशन कंट्रोलर का सिस्टम है। एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने वाले होते हैं और पढ़ाने वाले भी उसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। दोनों का दायित्व एक ही होता है, तो सेशन डिले होता है।

मेरा एक अनुरोध होगा, अगर सरकार इस पर विचार कर सके कि जैसे सभी स्थानों की परीक्षा अलग होती है, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को शिक्षा से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, ताकि उसकी डेट निर्धारित हो और वे परीक्षा लें। बच्चे वहां पहुंचें। यूनिवर्सिटीज की जिम्मेवारी हो कि वे उनको पढ़ा कर भेजें। यह एक प्रस्ताव था। मैं अपने प्रस्ताव के साथ-साथ अपने विषय में आगे बढ़ूंगा।

महोदय, उद्देश्य क्या होता है? आज हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में बनाने जा रहे हैं।

मैं इसी सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं। शायद माननीय मंत्री जी के राज्य में एक ऐसा स्थान है, मैं कभी वहां गया था, तो देख कर आया हूं। A Member of Parliament in this House has a college. जिसमें 80 हजार ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी क्लास से लेकर 80 हजार बच्चे बढ़ते हैं। वहां उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। वहां उनके खाने और कपड़े की व्यवस्था है। हमारे एक माननीय सांसद अच्युतानंद जी है, जो इनके भी मित्र हैं। उसके पीछे चाहे जो भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन इस देश में 80 हजार बच्चों को एक व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। इस देश में वैसा भी है कि शिक्षा एक व्यवसाय है। इस सदन में तो नहीं, ?* वैसे-वैसे भी लोग आए, जिन्होंने शिक्षा जगत में हजारों करोड़ रुपए कमाए। मैं उन पोलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वे माननीय सदस्य हैं। इस देश में वैसे भी लोग हैं, जो शिक्षा जगत से इतना धन अर्जित करके आए हैं कि आज वे ? में पहुंचे हैं, उसका कारण स्पष्ट है।?(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): : आप राज्य का नाम ले सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : वे पंजाब से हों, दिल्ली से हों, उसमें कई लोग जेल चले गए। मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। उसी संस्कार से वैसे लोग आए हैं। जो आज ? में पहुंचे हैं। हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे।?(व्यवधान) जिस राज्य में वह यूनिवर्सिटी है?

श्री भर्तृहरि महताब : आप उस राज्य का नाम ले सकते हैं**,** जिस राज्य में वह यूनिवर्सिटी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : वह ओडिशा में है। उस व्यक्ति और उस राज्य का भी उसमें जरूर श्रेय जाएगा, क्योंकि उस राज्य में 80 हजार बच्चों को पढ़ाने वाला विश्वविद्यालय है। अगर आपको मंदिर देखना है, तो वह विश्वविद्यालय जा कर देखिए, जहां गरीब, छोटे-छोटे बच्चे अपने कपड़े भी ठीक से पहन नहीं पाते हैं**,** वहां वैसे 80 हजार बच्चे नि:शुल्क पढ़ते हैं। खाना खिलाना और कपड़े देने की भी वहां व्यवस्था है। वे इस सदन के माननीय सदस्य हैं। वे दिखते भी नहीं है और बोलते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। औपचारिक शिक्षा के बारे में यूनिवर्सिटी में बात होती है। आप बिहार की शिक्षा के हालात के बारे में जानते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा होती है, तो पहली लड़की ऑल इंडिया टॉपर, दूसरी लड़की ऑल इंडिया टॉपर, चाहे वह इशिता हो या गरिमा हो, वे दोनों बिहार की लड़कियां हैं। जहां सेशंस लेट हैं, जहां परीक्षा कठिनाई से होती है। मैंने आपको दो उदाहरण दे दिए कि आखिर में किस प्रकार से होता है?

महोदय, आज भारत की सरकार और देश के प्रधान मंत्री जी ने एनईपी के तहत एक बड़ी नीति लाई है। उन्होंने उसे एंडोमेंट कहा। अगर हम इसे हिंदी में कहे तो चंदा होता है। अगर आप देखना चाहे कि इस देश में आज

की तारीख में बड़े विश्वविद्यालय को चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। जब से यह नीति लागू हुई है, तब से आईआईएम, दिल्ली, मुंबई-दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंडोमेंट आया, वे 160 करोड़ रुपए हैं। मैं दुनिया के वैसे संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहूंगा, जहां बच्चे पढ़ कर इस देश और दुनिया में बड़े होते हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 50 बिलियन यूएस डालर, लगभग चार हजार करोड़ वहां पास किए हुए विद्यार्थी, उस इंस्टीट्यूशन को देते हैं।

टेक्सास यूनिवर्सिटी, युनाइटेड स्टेट्स ? 42 बिलियन यूएस डॉलर, वहां से पास किए हुए विद्यार्थी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए देते हैं। They gave 41 billion US dollars as an endowment to the university they have passed out from. Look at the number of 36 billion US dollars. हमारी भी सरकार खर्च करती है। हम सब लोग सरकार के पैसे से ही इस देश की शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं कि जहां बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं। भारत में भी एक और चीज हो रही है। एक तरफ हम पढ़ाई की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो। लेकिन हम लोगों ने टॉप-हेवी कर दिया है। दुनिया में विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए इतने बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा यह प्रेरणा रहती है कि हम विश्वविद्यालय में परीक्षा दें। दुनिया में 10 प्रतिशत लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाकी अंडर ग्रेजुएशन करते हैं। हम लोग जो भी शिक्षा की नीति बनाते हैं, यह मूलत: इसलिए बनाई जाती है कि शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट जुड़े और वही आधार होता है। एक से दो प्रतिशत लोग अपने रोजगार में जाते होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य शिक्षा का यह है कि उसको एम्प्लॉयेबल बनाया जाए। क्या यह सवाल उठता है? अगर हम देश की परीक्षा को देखें, आज अगर मेरिट की बात हो, तो कायदे से पहले एक समय होता था कि परीक्षा की डिग्री लेकर जाइये और मार्क्स पर नौकरी ले लीजिए। उसे खत्म किया गया, क्योंकि उसकी गुणवत्ता में निरंतर गिरावट थी और उसी का परिणाम है कि आपने केन्द्रीय परीक्षा सेवाएं शुरू कीं, राज्य की परीक्षा सेवाएं शुरू कीं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जहां की शिक्षा अच्छी है, चाहे देश का आईआईटी हो या आईआईएम हों, वहां क्या हो रहा है? आज यूपीएससी में 70-80 प्रतिशत वे कैंडीडेट्स हैं, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो आईआईएम से पास कर रहे हैं। आखिर में गुणवत्ता तो वही है कि जहां शिक्षा अच्छी होती है, वहां रोजगार अच्छा मिलता है। उसका जीता-जागता परिणाम है कि देश के 50 से 60 प्रतिशत यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस और अन्य परीक्षा में पास करने वाले लोग इन्हीं संस्थाओं से पास होते हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए हम कहते हैं कि इस पूरे विषय को, अगर हम दूसरे रूप से देखें, क्योंकि हम लोग भारत में विश्वविद्यालय खोलते हैं, भारत के विश्वविद्यालय में तैयारी करवाते हैं, भारत के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति करते हैं, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में एम्प्लॉयबिलिटी का अभाव दिखता है, जिसका हमें निश्चित रूप से निदान निकालना चाहिए।

महोदय, शिक्षा के बारे में देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए? आपने मुझे बोलने के लिए समय कम दिया है। शिक्षा का अंतिम स्वरूप यह होना चाहिए कि शिक्षा देश में एक अच्छा नागरिक पैदा करे। लेकिन उससे भी बड़ा शिक्षा का स्वरूप होता है, जो कई बार पढ़े-लिखे लोग भी नहीं करते हैं, अगर शिक्षा आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, तो उससे बड़ी शिक्षा धरती पर कोई नहीं होती है।

इन चंद शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अच्छा इंसान बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए। यह मेरा सोचना है। धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): While supporting the Bill, I must also raise my concerns about the disappointing situation in which the SC and ST students and research scholars of this country are going through.

The House was stunned into silence as an answer given yesterday exposed and revealed the alarming dropout rate of students belonging to the SC and ST community and OBC category from Central universities and higher education institutions such as IITs and IIMs in the last five years alone.

The shocking data revealed that about 13,500 students of the SC, ST and OBC students have dropped out and stopped studying without completing their courses in the last five years. The dataset reveals that from the Central universities, the total dropout number in the last five years with regard to SC students is 2,424, ST students is 2,622, and OBC students is 4,596. They all have discontinued their studies.

In IITs, the dropout number with regard to SC students is 1,068, ST students is 408, and OBC students is 2,066. And for IIMs, the dropout number with regard to SC students is 163, ST students is 188 and OBC students is 91 students.

This data is for the last five academic years, and we can only imagine in absolute disappointment that the figures would be much higher in coming years as discrimination from students as well as faculty members against Scheduled Caste, Scheduled Tribe and

Other Backward Class students has increased in these days of hatred and intolerance being promoted by the Government itself.

Sir, it is also important to note that the number of students who committed suicide in IIMs and IITs in the last year is 33, and the number of students who committed suicide in higher education institutions between 2014 and 2021 stood at 122. This is not a small number by any means. So, instead of establishing a university and creating another unchecked avenue for discrimination, it is important that effective mechanism against caste discrimination is established. The universities and higher education institutions have become increasingly hostile towards Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. What is the reason? Could it be pure hatred fuelled by the polarizing rhetoric of the Government that rewards such racists? If yes, then I must say on this holy day of remembrance of Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, the Government must take steps in preventing caste-based discrimination in the higher education campuses as a policy priority and ensure strict punishment to the bigots who divide people and push them to committing suicide in prestigious campuses. Many faculty members have become so senseless and shameless that they start justifying the discriminatory practices as normal. Therefore, I demand that every university, higher education institutions and colleges as well as IITs, IIMs and other such institutions must have active and dedicated bodies with quasi- judicial powers to deal with the menace of atrocities against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. And these communities must have representation from dalit academicians and eminent persons to ensure justice.

Sir, in Kerala we have one Central university. I propose that the Central University in Kerala must be named after Ayyankali, the famous social reformer from Dalit community. Apart from these points, I would further highlight the glaring lack of representation in University leadership by Dalits in the country. In many of the Central universities, among academicians, Vice Chancellors and other faculties there is no proper representation from the Scheduled Caste or Scheduled Tribe community. So, I would like to request the hon. Minister to ensure representation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

During the tenure of the previous Government, a Committee was constituted in the higher education sector. Academicians, Members of Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were there. But that Committee was abolished. When that Committee was there, we had discussed various issues. There were representatives from IITs, IIMs, UGC as well as other academicians. That chance is gone because this Government came to power and that Committee was abolished. So, I would like to request the hon. Minister to reinstate that higher level Committee in the Ministry to discuss the various issues from time to time in various higher education institutions.

Sir, I am not going into all the details. I would further request that the Government must take steps to increase the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Vice Chancellors in universities, and there must be a system of mandatory provisions that would ensure Dalit academic leaders in universities in India. In many of the Central universities, there is no Vice Chancellor from Scheduled Caste and Scheduled Tribe community. I will request the hon. Minister to seriously consider this issue. I would also like to take this opportunity to pay my last respect to Dr. Kunjaman, an eminent Dalit scholar who faced discrimination and talked about institutional discrimination in Kerala.

Dr. Kunjaman was a towering figure in the academic circles who was denied an opportunity for growth as the wall of discrimination prevented an access and denied him opportunities. Such types of Scheduled Caste and Scheduled Tribe economists and also prominent Dalit academicians are denied an opportunity throughout India. I would also request the Government, through your good self, to ensure filling vacancies of Assistant Professors and Associate Professors from SC, ST communities in higher education institutions and Central universities as the huge gap that exists in filling vacancies is denying them their rightful opportunities. I would also request the Government to declare the present status and position of the steps taken for filling up the vacancies and for creating vacancies in these institutions. With these words, once again, I would request the hon. Minister to take necessary steps to protect the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students as well

as the eminent academicians from Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Universities.

Thank you, Sir.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, धन्यवाद।

माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा तेलंगाना में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया, उसका मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैं आपको केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह विधेयक तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। महोदय, यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रदान करेगा। यह देश में आदिवासी कला, संस्कृति और रीति-रिवाजों में शिक्षण और अनुसंधान संविधाएं प्रदान करके उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा देगा। महोदय, विविधता में एकता भारत की जनसंख्या की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.9 प्रतिशत है। पूरे देश में जनजातीय लोगों के पास अद्वितीय जीवन शैली और रीति-रिवाजों के साथ समृद्ध परम्पराएं, संस्कृतियाँ और विरासत है। महोदय, जनजातीय आन्दोलन भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अध्याय हैं। गोंड महारानी वीर दुर्गावती की वीरता हो या रानी कमलापति का बलिदान, देश इसे भूल नहीं सकता। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले और बलिदान देने वाले वीर भीलों के बिना वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे कई आदिवासी नायक हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 5 नवम्बर, 2021 से महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगवान बिरसा मुंडा की जयन्ती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भी लॉन्च किया गया है। केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इसके लिए मैं

केन्द्र सरकार का अभिनन्दन करता हूँ। महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय नामक एक ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। महोदय, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में जनजातीय लोगों की साक्षरता दर केवल 65 परसेंट है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए ताकि महाराष्ट्र के जनजातीय लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): सभापति जी, मैं सैंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल का मकसद तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना है जो सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाएगी। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इसका मकसद तालीम देना है और तालीम रोजगार के मवाके पैदा करने में कंट्रीब्यूट करेगी। इसका एंड ऑब्जेक्ट रोजगार के मौके पैदा करने का है। इस साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेढ़ करोड़ सय्याह जम्मू-कश्मीर में आए और आने वाले वर्षों में इनकी तादाद में इज़ाफा होने की तवक्को है। माना जाता है कि शायद अगले साल जैसे सरकार की उम्मीदें हैं कि तीन करोड़ के करीब सय्याह जम्मू-कश्मीर का रुख करेंगे। मेरा कहना है कि इस आमद के साथ-साथ जहां एकोमोडेशन है, होटल्स हैं या अन्य अरेंजमेंट्स हैं, उनमें बढ़ोतरी की एक तवक्को है। टूरिज्म इंडस्ट्री को, होस्पिटैलिटी को जो मैनपॉवर की जरूरत होती है, तीन करोड़ सय्याहों या चार करोड़ सय्याहों के लिए जो व्यवस्था है, इंतजाम करना या देख-रेख करना है, उसमें भी बढ़ोतरी की तवक्को है। जो होटल रूम्स हैं, उनमें भी कई सौ गुना इजाफा होगा और साथ-साथ जो ट्रेंड मैनपॉवर टूरिज्म इंडस्ट्री में है, उनकी संख्या में भी इजाफा होगा। आप सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 के तहत भारतीय सरकार यह अहतमाम करती हैं कि जो नेग्लेक्टेड सैग्मेंट्स हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी कायम हो ताकि इस इंडस्ट्री की जो भी जरूरतें हैं, वे भी पूरी हो सकें। मेरा कहना है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत एक टूरिज्म, होस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी अनंतनाग, कश्मीर में कायम की जाए ताकि हमारी मैनपॉवर के जो तकाजे होंगे और आने वाले समय में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, वे पूरी हो सकें। इस वक्त तक हमने ऐसी डेडीकेटेड यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। अनंतनाग में पहलगाम भी है, बेरीनाग भी है, रिजार्ट्स हैं, और आपको मालूम है कि तीर्थ यात्री, डेस्टीनेशन टूरिज्म, ईवेंट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और कई तरह के अन्य टूरिज्म के डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। दिन प्रतिदिन डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, बाहर का टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैनपॉवर की कमी है। कश्मीर के अलावा कोई जगह सारे मुल्क में नहीं है, जहां टूरिज्म और होस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी को

एस्टेब्लिश किया जाए और हम टूरिस्ट्स को ज्यादा सुविधाएं दे सकें, इसके लिए मैनपॉवर की जरूरत होगी। विदेशी टूरिस्टों से फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है और डोमेस्टिक टूरिस्ट्स से हमारी लोकल इकोनॉमी को फायदा मिलता है। मेरा सुझाव है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 के तहत एक होस्पिटेलिटी एंड टूरिज्म होस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी का एहतमाम किया जाए। इसके लिए प्रपोजल किया जाए, जो अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर में एस्टेब्लिश हो और आने वाले जो तकाजे या चैलेंजेज हैं, हम उन्हें एड्रेस कर सकें। मुझे नहीं लगता कि सिंगापुर में या दुनिया के दूसरे देशों में होस्पिटेलिटी हमारे से ज्यादा एहतमाम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत या आपत्ति होनी चाहिए। मंत्री जी यहां मौजूद हैं। एक तो आप सहूलियात पैदा कीजिए, ट्रेंड मैनपॉवर मुहैया कराएं और साथ-साथ ही रोजगार का बंदोबस्त कीजिए, यही तालीम का एंड ऑब्जेक्ट है। मैं इस सुझाव के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): چیرمین صاحب، میں سینٹرل یونیورسٹیز امینڈمینٹ ایکٹ، 2023 کی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ اس بِل کا مقصد تیلنگانہ میں ٹرائبل یونیورسٹی بنانا ہے جو سممکا ساراکا مرکزی جن جا تئے یونیورسیٹی کے نام سے جانی جائے گی۔ جیسا معزّز ممبر نے کہا کہ اس کا مقصد تعلیم دینا ہے اور تعلیم روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں کنٹریبیوٹ کریگی۔ اس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا ہے۔ اس سال سرکاری آنکڑوں کے مطابق ڈیڑھ کروڑ سیاح جموں کشمیر میں آئے اور آنے والے سالوں میں ان کی تعداد میں اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ مانا جاتا ہے کہ شاید اگلے سال جیسے سرکار کی امیدیں ہیں کہ تین کروڑ کے قریب سیاح جموں کشمیر کا رُخ کریں گے۔ میرا کہنا ہے کہ اس آمد کے ساتھ ساتھ جہاں ایکوموڈیشن ہے، ہوٹلز ہیں، دوسرے انتظامات ہیں، ان میں بڑھوتری کی ایک توقع ہے۔ ٹورزم انڈسٹری کو، ہوسپِٹیلیٹی کو جو مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، تین کروڑ سیاحوں یا چار کروڑ سیاحوں جو انتظامات ہیں، انتظام کرنا یا دیکھ ریکھ کرنا ہے، اس میں بھی بڑھوتری کی توقع ہے۔ جو ہوٹل رومس ہیں، ان میں بھی کئی گُنا اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ٹرینڈ مین پاور ٹورزم انڈسٹری میں ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ سینٹرل یونیورسٹی ایکٹ 2009 کے تحت بھارتیہ سرکار یہ اہتمام کرتی ہے کہ جو نیگلیکٹڈ سیگمینٹس ہیں، وہاں پر یونیورسٹی قائم ہو تاکہ اس انڈسٹری کی جو بھی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں۔ میرا کہنا ہے کہ سینٹرل یونیورسٹی ایکٹ کے تحت ایک ٹورزم ہوسپِٹیلیٹی یونیورسٹی اننت ناگ، کشمیر میں

قائم کی جائے تاکہ ہماری مین پاور کے جو تقاضے ہوں گے اور آنے والے وقت میں جو ریکوائرمینٹ ہوگی وہ پوری ہو سکیں۔ اس وقت تک ہم نے ایسی ڈیڈیکیٹڈ یونیورسٹی نہیں بنائی ہے۔ اننت ناگ میں پہلگام بھی ہے، بیری ناگ بھی ہے، ریزورٹس ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تیرتھ یاتری، ڈیسٹِنیشن ٹورزم، ایوینٹ ٹورزم، میڈیکل ٹورزم اور کئی طرح کے مختلف آسپیکٹس ہیں۔ دن بہ دن ڈومیسٹِک ٹورزم بھی بڑھتا جا رہا ہے، باہر کا ٹورزم بھی بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مین پاور کی کمی ہے۔ کشمیر کے علاوہ کوئی جگہ پورے ملک میں نہیں ہے، جہاں ٹورزم اور ہوسپِٹیلیٹی یونیورسٹی کو قائم کیا جا ئے۔ اور ہم ٹورسٹ کو زیادہ سہولیات دے سکیں اس کے لئے مین پاور کی ضرورت ہوگی۔ غیر ملکی ٹورسٹوں فورن ایکسچینج حاصل ہوتا ہے اور ڈومیسٹک ٹورسٹوں لوکل ایکونومی کو فائدہ ملتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ سینٹرل یونیورسٹی ایکٹ 2009 کے تحت ایک ہوسپِٹیلیٹی اینڈ ٹورزم ہوسپِٹیلیٹی یونیورسٹی کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لئے پروپوزل کیا جائے، جہ اننت ناگ، جموں کشمیر میں قائم ہو، اور آنے والے جو تقاضے یا چیلینجز ہیں ہم انہیں ایڈریس کر سکیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ سنگاپور میں یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہوسپِٹیلیٹی کا ہمارے سے زیادہ اہتمام ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو کوئی دِقت یا اعتراض ہونا چاہئیے۔ منتری جی یہاں موجود ہیں۔ ایک تو آپ سہولیات پیدا کیجیئے، ٹرینڈ مین پاور مہیا کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کا بندوبست کیجیئے، یہی تعلیم کا اینڈ اوبجیکٹ ہے۔ میں اس مشورے کےساتھ اس بِل کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں

(ختم شد)]

_

15.00 hrs

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Mr. Chairman, Sir, any decision, any Bill that aims at promoting education in the country is always welcome. The Central University (Amendment) Bill, 2023 which aims at establishing a University specifically and specially for

the tribal population is definitely a welcome move and the basic idea behind it is to provide avenues of higher education and research facilities among the tribal population.

Mr. Chairman, there are over 800 tribes in this country and we value their contribution in our growth story. At a time, when we are establishing one more university, we need to ask some tough questions. Mr. Minister, there are 1,182 universities in this country out of which 56 are Central Universities. Why is it so that none of these, we have 1,182 universities, universities feature among the top 200 universities of the world? Not a single one is among the top 200 universities of the world and among them, we have even 56 Central Universities. We proudly claim that we have 56 Central Universities. Our only university that features is ranked somewhere around 320. So, the big question is, are we not compromising on quality and stressing more on quantity कि देखिए हमारी सरकार ने कितने सारे विश्वविद्यालय, कितने सारे कॉलेजेज़ खोल दिए। We need to compete at the international level.

Mr. Minister, can you apprise us of the number of Scheduled Tribe students who are availing higher education? Is it not a fact that just like the Muslim community, the Scheduled Tribes have the highest number of drop outs in this country, almost about 25 per cent? Please correct me if I am wrong. Is it not a fact that those Scheduled Tribe students who have got all the education are not getting jobs because of the contractual system that you have adopted? So, there is no question of reservation for SCs/STs because there is a new contractual system. I admit there have been a number of Commissions and Committees that were constituted by the Government to address the economic and social plight of the Scheduled Tribes and education of the tribal population. Why is it that it continues to be dismal Mr. Chairman?

Is it not a fact that 19,000 SC, ST and OBC students have had to drop out of the premier institutes like IITs, IIMs and Central Universities. What was the reason? Among those 19000 students, 2,622 students were ST students. Is it because of the rampant casteism and discriminatory practices which is why 32 students from these elite institutes

committed suicide? This data was provided to us by the Union Minister of State for Education Subhash Sarkar in April, this year.

Mr. Chairman, Sir, I was listening to a number of speakers from the Ruling Party yesterday. I would especially like to mention one lady Member of Parliament who proudly said that see it is our Government, the Government of Mr. Narendra Modi that made Mr. A.P.J. Abdul Kalam, a Muslim, the President of India. No, he deserved that place, which is why, he rose to the rank of the President of India. Then, she said that we made a Scheduled Caste, Mr. Ramnath Kovind the President of India. He deserved that. What have you done for their community? The third thing that she said was this. She very proudly said we made a Scheduled Tribe, a tribal woman as the President of India. Mr. Minister, I would like to ask one question. The President of India lives next to this palatial building that has been built by you. My question to you is this. Why was she not invited for the inauguration of this Parliament building? She happens to be the custodian of the Parliament building. She lives next door and there were heroines that were roaming around in this Parliament building when it was inaugurated and you do not invite a tribal President of India.

Mr. Chairman, Sir, I would just conclude by saying कि आपने एक ट्राइबल महिला को कुर्सी तो दे दी, पर उस समाज को सम्मान देना भी सीखिए।

धन्यवाद।

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Thank you, hon. Chairman, Sir.

I rise to support the Central University (Amendment) Bill, 2023 जिसके माध्यम से हम तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहे हैं। मैं तेलंगाना के ट्राइबल्स की ओर से और देश भर के ट्राइबल्स की ओर से मोदी साहब, धर्मेन्द्र प्रधान और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप ट्राइबल्स के लिए एक और सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं।

साथ में लैण्ड एलॉटमेंट हो गया और पैसा भी एलॉट हो गया है। Within three-four years, the tribal community is going to enjoy the benefits of this Central Tribal University in Telangana. मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में कौन जाएंगे? इसमें क्लास वन से बीए तक की पढ़ाई पास कर के ही छात्र जाएंगे। Tribal society and tribal community need to be studied very deeply. The dropout rate from class 1 to class 10 is almost 70 per cent. इसका कारण क्या है? Lack of socio-economic development और दूसरा, ये घने जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। इन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए मोदी साहब ने एक स्टेप लिया। फ्री राइस बीपीएल लोगों को देने के कारण इनकी लाइफ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मोदी साहब ले कर आए हैं। अब ट्राइबल छात्रों को शिक्षा में आगे ले जाने के लिए यह यूनिवर्सिटी हेल्पफुल होगी। अगर उनके कल्चर और सोश्यिो-इकोनॉमिक डेवल्पमेंट को साथ में नहीं जोड़ेंगे तो हमारे ट्राइबल छात्र पीछे रह जाएंगे। उनको बहुत दूर-दराज़ से स्कूलों में जाने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि एक ऐसी ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसमें आईटी की सुविधा और फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई भी हो। साथ ही, हर्बल मेडिसिन की स्टडीज़ भी इसमें हो, क्योंकि मैं सदन को भी बताना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिया में जड़ी-बूटी से मेडिसिन बना कर टूटी हुई हड्डी जोड़ दी जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में टीटी इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन गांव में हर्बल मेडिसन से यह काम हो जाता है क्योंकि यह हर्बल मेडिसिन हम ट्राइबल्स के बीच में है। वहां इस पर भी स्टडी होनी चाहिए। साथ में, स्पोर्ट्स की सुविधाएं पूरी तरह से होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर से आने वाले माननीय सदस्य मसूदी साहब ने ठीक कहा कि इसी यूनिवर्सिटी में टूरिज्म और हॉस्पिटेलिटी की पढ़ाई भी होनी चाहिए। साथ में यहां ऐसा एटमोस्फेयर हो, इसका ईको सिस्टम ऐसा हो कि tribals should not feel isolated after having the Central Tribal University in Telangana. वहां ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि फॉरेन लैंग्वेजिस की भी स्टडी होनी चाहिए। साथ ही, आईआईएम और आईआईटी की सुविधा भी उस यूनिवर्सिटी में हो। जब तक हम ट्राइबल्स के साथ दूरियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक यह सफल नहीं होगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में we need to incorporate the tribal cultures and tribal values. तब जा कर हमारे ट्राइबल्स वहां जा कर अपनापन महसूस करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे

मैं माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करुंगा आज कोचिंग बिज़नस को हम कैसे बंद करें? जैसा कि रूडी साहब ने भी इसका उल्लेख किया है। कोचिंग बिज़नेस के कारण हमारे ट्राइबल लोगों के पास उसकी फीस देने लायक पैसा नहीं होता है और इसलिए ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है and they are bound to be the bonded labour in other parts of the country. इसलिए ट्राइबल्स को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए, मोदी साहब के सपने को साकार करने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए कोचिंग सेंटर की जगह पर तेलंगाना

सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम की कोचिंग की भी सुविधा होनी चाहिए, ताकि हमारे ट्राइबल छात्र वहां आईएएस और आईपीएस के लिए फ्री शिक्षा पा सकें। हमारा यह टारगेट इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए।

सर, मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा। हम ट्राइबल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देते हैं, लेकिन आज तक 225 रुपये से कभी आगे नहीं बढ़े हैं। आज हम एक ट्राइबल स्टूडेंट को एक महीने में 225 रुपये की स्टाइपेंड देते हैं। यह हमें कहाँ तक सहायता दे सकता है, इससे हम न अच्छे किताब खरीद पाएंगे, न ही खाने-पीने की कुछ अच्छी चीज मिल पाएगी। इस 225 रुपये से हमारे ट्राइबेल स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए, मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस 225 रुपये से आगे बढ़ने का एक प्लान बनाइए। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, ताकि जंगल और पहाड़ों में रहने वाला ट्राइबल स्टूडेंट आगे आ जाए।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस मौके पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को ?वन नेशन वन सिलेबस? पॉलिसी के बारे में भी सोचना होगा। जब तक देश में ?वन नेशन वन सिलेबस? नहीं होगा, तब तक इंटेग्रिटी और देश की ताकत में कमी आएगी। पूरे देश का एक ही सिलेबस हो, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ेंगे, तमिलनाडु के लोग तमिल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही सिलेबस हो। Then, there would not be any discrimination among the students of the society. ?वन नेशन वन सिलेबस? के अभाव में आज हमारे देश के हर स्टेट में अपना-अपना बोर्ड है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और ट्राइबल के स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पीछे रह जाते हैं।

मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब और सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि देश में ट्राइबल्स आईआईटी और आईआईएम इंस्टीट्यूट में भी आने चाहिए। इस कॉम्पिटिशन में हमारे एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूं। इस देश के हर कोने में आईआईटी, आईआईएम और ट्राइबल इंस्टीट्यूट्स भी होने चाहिए।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ ही असम में भी 30 परसेंट ट्राइबल्स हैं। हमारा नॉर्थ-ईस्ट रीजन एक ट्राइबल जोन है। इसलिए, मैं ऑनरेबल मोदी साहब और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी पूरे नॉर्थ-ईस्ट रीजन के लिए एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए, for the entire North-Eastern Region because Arunachal is no more a backward State. अभी यह एयर से कनेक्टेड है, रेलवे से कनेक्टेड है, मोदी साहब ने चाइना बॉर्डj तक टू लेन रोड बनाया है। इसलिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हमारे

अरुणाचल प्रदेश में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाए। थैंक यू, सर।

***m11 PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Sir, I rise to support the Central Universities (Amendment) Bill which envisages setting up of a tribal university in Telangana possibly in Warangal which is a district town of Telangana. The Minister must be lamenting why this Bill was not passed earlier. If it was done before Telangana elections, maybe his party would have got a few more seats. But that is neither here nor there. Mr. Dharmendra Pradhan, as the HRD Minister, is in control of the best institutes of India like IIT, IIM, and IISER. They are all under him.

So, here is really an opportunity of improving the quality of higher education in India. It is a matter of some wonder that in spite of all the money allotted, none of the Indian Institutes are among the top 200 institutions in the world. What can we do to improve the academic standards and make them comparable to the universities in England, America, France and even Singapore, leave alone China? That is the main question. Anyway, he has proposed this university for tribals. He is eminently suitable because he was a student of anthropology, and the study of tribals is done in anthropology. There is social anthropology, political anthropology which should be studied.

Mr. Mahtab gave me one idea. As has been mentioned by Kumari Agatha K. Sangma, in the North-Eastern Hill University, local languages like Khasi and Garo are taught. So, in this Tribal University, I hope, the tribal languages like Santali and Mundari will be taught. My idea is, since you are spending so much money, let the university be set up at one place but it can have campuses in several tribal dominated areas. For example, in Bengal, we have two tribal dominated areas ? Jhargram and Dooars. If we set up some campuses outside, this will also give a boost to tribal education. But may I mention that in spite of striving for excellence in central universities, the situation is still bad. The cases of suicides are taking

place among students in these higher education institutes. Students are dropping out of their courses.

Sir, we have a University called the University of Hyderabad in the State of Telangana. We all know about the suicide case of Rohith Vemula. It rattled the whole country how a Scheduled Caste boy felt so frustrated in a Central University that he had to commit suicide. It created a lot of dispute in the whole country.

Mr. Minister is from Odisha. In Odisha, one Central University was set up in Koraput which is totally a tribal dominated district. But it has no faculty at all. I know a lady who used to be the Vice Chancellor and never went to Koraput. She used to commute from Kolkata to Bhubaneswar and back. I will request the hon. Minister to give attention to this University in tribal dominated area in his own home State. ? (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): That Vice Chancellor was during the UPA regime. ? (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Whatever it is, let him have a good Vice Chancellor. There is nothing to prevent it. He has got all the power.

The other thing is, there are 36 Central Universities but I often hear a complaint that the scholarships given to the students are not sufficient. Some students from Puducherry approached me. There is a Central University there. They said that they ask their parents to send money to them so that they can continue their research. If you want to improve the quality of research, then you have to increase the scholarship amount.

Further, I would say that it is a good idea as I said, but the Minister has the chance. Now he is also a very important man in his own Party. He has got a decent clout. Let him put his clout to good use for the improvement of the central institutions. Some of the central universities are very good like the Delhi University and the JNU. They are very good. They are high standard universities. Even the Hyderabad University is also very good. But some universities are not up to the mark.

Lastly, I will ask him one thing. There is a single central university in West Bengal. In 1857, that was the first university in Calcutta. But Visva-Bharati is in shambles. The last Vice-Chancellor, who claimed to be close to the BJP, has destroyed it. Now he had even set up a flex board depicting Visva-Bharati being given a heritage status by the UNESCO. Only the names of the Vice-Chancellor and the Prime Minister were there. The name of Rabindranath Tagore was not there. Now that has been removed by the local people. But why did Mr. Dharmendra Pradhan not remove it? Why did they allow the Vice-Chancellor to run riot? Will there be an inquiry held against the previous Chancellor over his acts of omission and commission?

As I said, I support this Bill. The tribal people deserve even more. We have not been able to give them enough, at least, educationally. If we can improve their condition, if we can keep the tribal students in the campuses, prevent their suicides, and give them more scholarships, then it would be a good thing. In this regard, I remember the contribution made by Mr. Bibhu Prasad Das who did a study of the tribes in the North-East. He suggested setting up of universities for the tribals. You can go into the archives and look into his recommendations. Due to his recommendations, the North-Eastern Hill University (NEHU) was formed just as the Rabindranath Tagore?s Institute was converted into a Visva-Bharati Central University with Jawaharlal Nehru?s intervention.

With these words, I again support the Bill which is a forward step towards uplifting the cause of the tribals in this country. Thank you, Sir.

***m12 DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM):** Sir, thank you for giving me this opportunity to take part in this very important discussion. I think we have to approach the very concept of university with a comprehensive outlook. As this very concept of knowledge is universal, we have to approach the concept of university also with a universal mind and a universal attitude. Now-a-days, there is an increasing tendency of reducing and

limiting knowledge to the corridors of subjects. That is growing as an unhealthy tendency. I would like to draw the attention of the hon. Minister and this august House to the recommendations and the suggestions made by the Yash Pal Committee in this regard. The trend of universities limiting to a singular subject, for example, medicine, engineering, teachers? education, sports, etc., will not be fruitful for realising the very aims and objectives of the universities. It may be bringing administrative convenience but it will not help the academic accommodation of different subjects thereby opening the horizons of knowledge into various vistas of wisdom.

Sir, science, humanities, philosophy, aesthetics ? all have to be made available under the same umbrella, that means, various subjects, various disciplines in a singular centre. Sir, research experience in science may be leading to an area belonging to the realm of philosophy. Likewise, a philosophical quest may be ending in an arena of metaphysics or cosmology. Variety of subjects will only help the richness of a university. The world-famous linguist scientist, Noam Chomsky was working in Massachusetts Institute of Technology. Harvard University was founded by a priest named John Harvard. It was founded for theological studies. I mean, flourishing in their main subjects, these universities were spreading their wings to the horizon of plurality and variety of various disciplines. Nowadays, we have to look into our surroundings when we think of a new university. Humankind is going through unprecedented changes and revolutions. All our stories are crumbling. We should have a clearcut outlook, clearcut decision and solution ? what we should provide in a university, and what kind of skills we should inculcate in the coming generations, which should not merely be to get a job but to conquer life, to stand face to face with life.

Sir, I am reminded of a couplet of our famous poet Akbar Allahabadi ?

हम क्या कहें अहबाब क्या कार-ए-नुमायां कर गए

बी-ए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए।

This is what is happening nowadays. Just for a job - ?बी-ए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए।? आजकल तो पेंशन भी खत्म हो गई है।

Sir, what I mean, the university should have a higher aim of understanding life situations all around. Studying textbooks only will not be enough for our students. The student will have to make his own self, go beyond the text to the context of life. Our surroundings are flooded by not only information but misinformation, prejudices and a lot of irrelevancies. So, a healthy campus has to address these kinds of problems. A healthy campus can be made only by debates, dissents and by differences of opinion, and a culture of pluralism. Both knowledge and culture are composite. Knowledge is composite and every culture is essentially and basically composite. Various American universities teaching artificial intelligence and robotics are nowadays including ethics and philosophy in their curriculum, and in their research projects. We have to prepare the learners to foster ethical, rational, compassionate, caring and healthy individuals. What is happening nowadays all over the world is exploitation, injustice, social inequalities and even aggression and killings of innocent children and mothers in various parts of the world. Wherever it is happening and whoever is responsible for this catastrophe, their problem is not lack of education, their problem is not that they do not have any degree or any academic qualification, their problem is lack of humanity. So, we will have to rise above the caste, class, creed, gender, religion and language for realising a real campus, a real university. During the formation of a university, we will have to think above the commercial and economic levels - at the human level. Absence of humanity in the society should lead to a kind of idealism, multiculturism and pluralism. I have to request the hon. Minister to keep in mind the need of using emotional intelligence, utilising the ethos and norms of emotional education so that a kind of holistic education can be imparted, taking into consideration all aspects of the learner, including his mind, heart and soul.

With these words, I support this Bill. Thank you so much.

HON. CHAIRPERSON: Today, there is no concluding couplet!

***m13 श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख)**: धन्यवाद सभापति जी । मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा लाए गए इस बिल का स्वागत और समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करके स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिसको समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जाएगा। मैं देश की 8.6 परसेंट ट्राइबल कम्यूनिटी पॉपुलेशन की ओर से इसका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने ट्राइबल कम्यूनिटी के लिए 9 सालों के कार्यकाल में बहुत-कुछ किया है। एक फोकस्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करके जनजातीय समुदाय को हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ-साथ मॉर्डन एजुकेशन दिया। जिस तरह से अभी मेरे से पहले तापिर गाव साहब बता रहे थे कि हम सभी चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राइबल कम्यूनिटी का कल्चर, ट्रेडीशन, पहचान के बारे में तो स्टडी होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आधुनिकता हो, आईआईटी, आईआईएम हो, दुनिया भर की एजुकेशन ट्राइबल कम्यूनिटी को मिले तथा नॉन ट्राइबल कम्यूनिटी के लोग भी आकर ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करें।

महोदय, आज प्रधान मंत्री जी द्वारा इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम मां समक्का सरक्का देवी जी के नाम से रखा गया है, जिसके लिए हम सब धन्यवाद देते हैं। इससे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर से मनाना शुरू किया था। इसके जरिए भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा सभी ट्राइबल कम्यूनिटी को देते हुए और इस देश में ट्राइबल कम्यूनिटी के चाहे फ्रीडम फाइटर्स हों या इस देश को बनाने वाले हों, ट्राइबल कम्यूनिटी के योगदान को संवारा। इस बात के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन 9 सालों में ट्राइबल कम्यूनिटी के विकास के लिए वर्ष 2014 से 2023 तक 4 हजार 495 से लेकर 12 हजार 462 करोड़ रुपये का बजट केवल ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा खर्च किया, चाहे वह लोअर एजुकेशन के लिए हो, हायर एजुकेशन के लिए हो या ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो। उन्होंने इसके लिए बहुत-कुछ किया।

महोदय, मैं लद्दाख से आता हूं। लद्दाख की 96 परसेंट पॉपुलेशन ट्राइबल कम्यूनिटी से आती है। पूरे लद्दाख की कम्यूनिटी और ट्राइबल कम्यूनिटी भी चाहती है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसे ध्यान में रखते हुए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। लद्दाख के लिए अलग से बिल लाकर सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें दी गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख दी गई, इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इतना काम वर्तमान में लद्दाख की ट्राइबल कम्यूनिटी की एजुकेशन के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं इस बिल के माध्यम से

माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख कि किसी भी एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना बहुत जरूरी है।

मैं यह भी मांग करना चाहता हूं, मैंने जिस तरह बताया कि लद्दाख में ट्राइबल कम्युनिटी काफी हैं। उनमें से कुछ कम्युनिटी बहुत कम पॉपुलेशन में हैं, जैसे जो आर्यन कम्युनिटी, सिन्ना कम्युनिटी और बाल्टी कम्युनिटी हैं, ये अब खत्म होने के कगार पर हैं। इनकी आबादी बहुत कम है। आर्यन कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, पूरे देश और दुनिया से टूरिस्ट उनको अलग से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वे अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट हैं और उनका अलग-अलग इतिहास है। उनकी पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए, उनकी भाषा, पहचान और उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए लद्दाख में ट्राइबल रिसर्च सेंटर होना बहुत जरूरी है।

महोदय, साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि लद्दाख के इन ट्राइबल कम्युनिटीज को, जो खत्म होने के कगार पर हैं, जो वलनरेबल हैं, उनको यूनेस्को में इनटैंजिबल हैरिटेज के नाम से घोषित करें। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ओर से स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है। पूरे हिमालयन रीजन में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, वे ज्यादातर भोटी भाषा बोलने वाले लोग हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि भोटी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के साथ-साथ जो स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटीज की भाषाएं हैं, जैसे आर्य, सिन्ना, बाल्टी या पुरगी भाषा, ऐसी जुबानों को प्रमोट करने और प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से यह मांग रखता हूं।

महोदय, यहां शिक्षा की बात हो रही है तो मैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हालांकि, यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का विषय है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि देश में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को काफी संख्या में बढ़ाकर उनमें स्कॉलरशिप, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन, नये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसमें हिली एरियाज के लिए एक ब्लॉक में 20 हजार पॉपुलेशन होना आवश्यक है। यह हिली एरियाज में असंभव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं। मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे अरुणाचल प्रदश में 26 मेजर ट्राइब्स हैं, उनके यहां एक डिस्ट्रिक्ट है, जिनकी पूरी आबादी केवल पाँच-छ: हजार है। अब एक ब्लॉक में 20 हजार पॉपुलेशन हम कहां से लाएंगे? मेरे लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में तीन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं। उनकी कुल आबादी 13 हजार है। मेरे यहां नुब्रा में कुल 13-14 हजार पॉपुलेशन है। वहां पर भी तीन ब्लॉक्स हैं।

माननीय सभापति : नामग्याल जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : महोदय, हम चाहते हैं कि उस एरिया में जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, हमारे आर्यन वैली में, हमारे द्रास में, वहां पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए जितनी पॉपुलेशन की क्राइटेरिया रखी गई है, वह कभी फुलफिल नहीं होती है। उसके कारण हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से वंचित रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसके लिए क्राइटेरिया को थोड़ा रिलेक्स करके पॉपुलेशन की संख्या को कम किया जाए।

सर, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट है, मैं एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जब हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो लद्दाख में तीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज आते हैं, जो चांगतांग, नुब्रा और काराकोरम हैं। वे अभी बनने की प्रोसीजर में हैं। यह वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1987 द्वारा लाया गया है, जो अभी फाइनल स्टेज तक नहीं गया है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आईएफएस और आईएएस का ही झगड़ा है, जिसकी वजह से हमारे लोग सफर कर रहे हैं।

माननीय सभापति: वह अलग सब्जेक्ट है।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : सर, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं।

माननीय सभापति: वह अलग सब्जेक्ट है।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल : सर, मुझे डिमांड रखने दीजिए। मैं पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, केवल डिमांड रखूंगा। हिमीज नेशनल पार्क का टोटल एरिया 3 हजार 350 स्कॉयर किलोमीटर है, जिसको ग्राउंड पर 5 हजार स्कॉयर किलोमीटर रखा है। चांगतांग कोल्ड रिजर्व वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के लिए 4 हजार स्कॉयर किलोमीटर है, लेकिन ग्राउंड पर 18 हजार स्कॉयर किलोमीटर कैप्चर करके रखा है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के लिए 5 हजार स्कॉयर किलोमीटर है, लेकिन ग्राउंड पर 15 हजार स्कॉयर किलोमीटर कैप्चर करके रखा है। उससे केवल वहां के रेजिडेंट, डोमिसाइल, इंडिजेनस को ही नहीं बल्कि देश के स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी हमें दिक्कत हो रही है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसको रेशनलाइज किया जाए और जहां-जहां ह्यूमेन हैबिटेशन है, वहां इसको एक्सक्लूड करके एजुकेशन में आगे बढ़ने में हमें मौका दिया जाए। इकोनॉमी अफेयर्स में भी हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ? (व्यवधान)

***m14 डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) :** सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं और समाजवादी पार्टी हर उस बिल का सपोर्ट करती है, जिसमें तालीम

और एजुकेशन को बढ़ावा मिले। मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हमें मालूम है कि इस देश के लिए रक्षा के बाद शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं पिछले कुछ सालों से यह देख रहा हूं कि हमारा जो बजट है, वह शिक्षा के लिए कितना है और बाकी चीजों के लिए कितना है। मैं अफ़सोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का बजट 15 प्रतिशत कम कर दिया गया है, जबकि अन्य यूनिवर्सिटीज़ का बजट बढ़ा दिया गया है। मुझे इस पर ऐतराज़ नहीं है, उसे और बढ़ाएं। 15 प्रतिशत बजट कम करने की वजह से रिसर्च प्रोसेस, एजुकेशन और एकेडेमिक्स में समस्या आने लगी है।

महोदय, वर्ष 2014-15 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट 1,520 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में वह 1,214 करोड़ रुपये हो गया है। 306 करोड़ रुपये का बजट कम कर दिया गया है, जबकि जेएनयू का बजट 70 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। बीएचयू का बजट डबल कर दिया और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का फंड 250 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। मुझे उस पर ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इस पर ऐतराज़ है कि इस देश की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका बजट कम कर दिया गया है।

महोदय, आप यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, यह खुशी की बात है। आप 7 सालों तक लगभग 900 करोड़ रुपये देंगे। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। यहां सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है, यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा तो यह कहना है कि हर 2-3 मंडल में एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 3 प्रतिशत एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जैसा विकसित देश अपनी जीडीपी का 5 प्रतिशत खर्च करता है, जर्मनी 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है और साउथ अफ्रीका 7 प्रतिशत खर्च कर रहा है। इसकी वजह से उनके यहां डेवलेपमेंट तेजी से हो रहा है और शिक्षा बढ़ती चली जा रही है।

महोदय, मुझे मालूम है कि एजुकेशन इंसान को इंसान को बनाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हर यूनिवर्सिटी में मोरल वैल्यूज़ के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आज इंसान की मोरल वैल्यूज़ गिरती चली जा रही हैं। यहां पर पैरेन्ट्स-चाइल्ड रिलेशनशिप कम होती जा रही है। हमारे कल्चर में अपने मां-बाप की अदब और सेवा अनिवार्य है, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। देश की कम्युनल हार्मोनी कहां जा रही है**,** जिसकी आज देश को सख्त जरूरत है। हमारे देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो स्टूडेन्ट-टीचर्स रिलेशनशिप है, वह डेट्रिओरेट कर गई है। मां-बाप के बाद गुरु का दर्जा होता था, लेकिन आज लोग गुरु की ही पिटाई कर रहे हैं, उनका मर्डर कर रहे हैं। आज हम किस जगह पर पहुंच गए हैं?

महोदय, हम संस्थान बनाएं, लेकिन हम उन संस्थानों में कम से कम इंसान बनाएं, हिन्दुस्तानी बनाएं। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो हिन्दुस्तान दिया है, वह प्यार-मोहब्बत का हिन्दुस्तान, अपनी तहज़ीब का हिन्दुस्तान, एक-दूसरे के काम आने के जज़्बे का हिन्दुस्तान है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे संस्थानों से भी यही मैसेज जनता और हमारे बच्चों में जाना चाहिए।

***m15 डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) :** आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं अपनी बात इससे शुरू करना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने यह कहा था कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इससे जीवन उच्च बनता है, शिक्षा से व्यक्तिगत जीवन भी उच्च बनता है**,** समाज का जीवन भी उच्च बनता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे सभी क्षेत्रों में ऐसा कोई भाग न बचे, ऐसा कोई क्षेत्र न बचे, ऐसा कोई वर्ग न बचे, जिसको हम उच्च शिक्षा से विभूषित न कर सकें।

शिक्षा की जो महत्ता है, उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग बचपन में एक श्लोक याद करते थे **?**

न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि ।

व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ।।

ये धन ऐसा है, जिसको चोर नहीं ले जा सकता, जिसको राजा छीन नहीं सकता, जिसको भाई बांट नहीं सकता, जिसको जितना खर्च करते हैं, उतनी विद्या बढ़ती है। अगर दुनिया में कोई धन सबसे बड़ा है, अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, तो उसका नाम विद्या है, उसका नाम शिक्षा है।

सभापति महोदय, मैं कुछ मूलभूत बातें कहना चाहता हूं। जब से धरती पर मानव आया, हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अगर मानव का निर्माण करना है तो उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी हम कह रहे थे कि शिक्षा क्या हो, मैं इसलिए बताना चाहता हूं और यहां पर हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है ? ?सा विद्या या विमुक्तये?। शिक्षा वह है, जो हमको बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी से मुक्ति दिला सके और मुक्ति दिलाने के साथ-साथ एक अच्छा इंसान बना सके।

हमें ?मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्?, अर्थात् हमें अच्छा इंसान बना सके और हम अच्छे देवता समाज के अंदर पैदा कर सकें, वह शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है।

हम लोग कई बार कहते हैं कि हमें लंबाई नापनी हो तो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, अगर किसी चीज का वजन नापना हो तो किलोग्राम और टनों में नापना पड़ता है, अगर आदमी, किसी समाज की उन्नति, प्रगति का पैमाना नापना हो और किसी राष्ट्र की प्रगति का कोई पैमाना है तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा कि वह कैसा होना चाहिए और उसका पैमाना क्या है। उन्होंने कहा कि आदमी के आनन्द का सबसे पहला पैमाना क्या है, उसकी इकाई क्या है, उसकी डिजिट क्या है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली में यह बात आती है :-

युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्ठो दृधिष्ठो बलिष्ठ,

तस्येयं पृथिवे सर्व वित्तस्य पूर्ण स्यात्; सा एको मानुष आनन्दः।

हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो अच्छा चरित्रवान बना सके, अच्छे शिक्षक सुसंस्कृत बना सके, शरीर, मन, आत्मा से बलिष्ठ बना सके। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य है, जिससे सबसे पहले कोई भी देश नापते हैं कि देश कितना प्रगतिशील है। हम लोग कई बार अपने देश के बारे में बोलते हैं तथा नालंदा और तक्षशिला की बात करते हैं। नालंदा और तक्षशिला हमारे इतने बड़े विश्वविद्यालय थे, लेकिन मैं कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में यह बताना चाहता हूं कि यह वह तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो पाकिस्तान के गांधार के अंदर है। यह महाभारतकालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसमें ऋषि धौम्य के शिष्य उपमन्यु, आरुणि और वेद ने शिक्षा ग्रहण की। इस विश्वविद्यालय के अंदर चाणक्य, पाणिनी, चरक, जीवक और लगभग साढ़े दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे तथा दो हजार आचार्य होते थे।

सभापति जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तक्षशिला और नालंदा थे, उसी प्रकार से कल्हण-राजतरंगिनी में जिसने कश्मीर का इतिहास लिखा है, उसने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय था, जिसमें 15 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। गुजरात सौराष्ट्र का वल्लभी विश्वविद्यालय था, मगध का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ओडिशा के ओदन्तपुरी, जगदल्ला, उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी और कलिंग का पुष्पगिरी बहुत बड़े विद्यालय थे। इसी तरह से बंगाल के नवद्वीप, सोमपुरा, विक्रमपुर विद्यालय थे। नवद्वीप विश्वविद्यालय तो इतना प्रचलित रहा कि वहां से हलायुध, धोयी, उमापति और गीत गोविंद के लिखने वाले जयदीप जैसे विद्वान पैदा हुए। दक्षिण भारत के अंदर धारा, कांची, एन्नेरियम, बेलग्राम, सालोतगी, तिरुमुक्कुरल, मलकापुरम, तिरुवेरियूर, नगड़, भुजबलेश्वर, बीजापुर, मनगोली, अग्रहार, नागार्जुनकोंडा, मणिषेत जैसे बड़े-बडे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे।

कई बार हमारे लोग यह कहते हैं कि लोगों में एक इम्प्रेशन पैदा हो गया कि अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने यहां पर शिक्षा दी, लेकिन मैं इस सम्माननीय सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। उन्होंने वर्ष 1822 के अंदर एक सर्वे किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय गांव-गांव में पाठशालाएं थीं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे। उसमें 30 परसेंट शिक्षक दलित वर्ग से आते थे, 60 परसेंट विद्यार्थी शूद्र या पिछड़े वर्गों से आते थे। इसी तरह का सर्वे मुंबई में किया गया था। जी. एल. प्रेंडरगैस और डॉ. जी. डब्ल्यू लीटनर ने वर्ष 1838 और 1882 में मुंबई में सर्वे किया था। विलियम वार्ड ने एक पुस्तक लिखी है। कई बार हम बोलते हैं कि देश में लड़कियों के लिए जो शिक्षा शुरू हुई, वह सावित्री बाई फूले ने की थी, लेकिन उससे पहले एक अंग्रेज ने लिखा है और द हिन्दूज का फोर्थ वॉल्यूम हिस्ट्री लिटरेचर एंड माइथोलॉजी है, जो वर्ष 1811 में लंदन में पब्लिश हुई था। उसमें उन्होंने लिखा है कि जशोमतराय की पत्नी होती विद्यालंकार ने वर्ष 1805 में बनारस के अंदर शुरू किया। ?(व्यवधान) सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : सत्यपाल सिंह जी, आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह : वर्ष 1805 में उन्होंने इसको शुरू किया। मैं शिक्षा की बात कर रहा था। आर्य समाज ने वर्ष 1890 में जालंधर में केवल लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किया। इसी तरह से हमारे पास इतने उदाहरण हैं कि हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर विद्या की कितनी कीमत थी। हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं उनसे जरूर यह निवेदन करूंगा और भारत सरकार से भी एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल का नाम देते हैं, यह मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को पूरे देश की जनता को पांच प्रण दिलवाए थे और उस पांच प्रण में एक प्रण यह भी था कि गुलामी की सारी निशानी हमें खत्म करनी है। जब हम कहते हैं, यह आदिवासी है, इसका मतलब यह है कि बाकी सब गैर आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब यह है कि वे यहां के मूल निवासी हैं। गैर आदिवासी का मतलब यह है कि वे यहां के मूल निवासी नहीं हैं। यह जो डिविजन, यह जो विभाजन इस देश की जनता के साथ किया गया है, मुझे लगता है कि इस पर भी फिर से विचार करने की आवश्यकता है। यह बात शुरू हुई थी कि विल्हण ने जो बात शुरू की थी कि सिंधु घाटी में बाहर से लोग आए और आर्यों ने आकर सिंधु घाटी पर हमला किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। इस बात को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। इस थ्योरी को डिबंक किया जा चुका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं दो नाम जरूर लेना चाहूंगा- डॉ. रामजी सिंह, जिनको देश में डीएनए का फादर माना जाता है। उनका वर्ष 2011 नेचर पत्रिका, जो कि साइंस की प्रसिद्ध मैगजीन है, में इंडियन डीएनए का प्रोफाइल पब्लिश हुआ था। डॉ. वसंत शिंदे का वर्ष 2019 में पब्लिश हुआ था। हम सब लोगों का डीएनए एक ही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब लोग एक हैं। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से और यह निवेदन मैंने बागपत में भी किया था। हमारा

सौ साल से पुराना एक कॉलेज है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैंने उसके लिए निवेदन किया है, उसका उच्चकरण किया जाए और उसको सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m16 ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** Sir, thank you for giving me this opportunity. I am supporting the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 because the tribal population of the State of Telangana is very much benefited. The Central University Act, 2009 was a seminal legislation of the UPA Government that established 15 universities in one single go. The objective of the parent Act is to create autonomous Centres of learning that will become Centres of Excellence in due course. In that sense, in Kerala, we also got one Central University at Kasaragod, and it will also get benefited.

The Statement of Objects and Reasons of the Bill clearly states that the purpose of this Bill is to increase access and quality of higher education and facilitate and promote higher education and research facilities for the people of the State. It will also promote advanced knowledge by providing instructional and research facilities in tribal art, culture and customs, and advancement in technology to the tribal population of India.

The tribal population of India is the most marginalized and backward community in India. Hence, studying their life, art, culture and customs is integral to ensuring inclusive development in our nation. This is true for the tribals from Kerala as well.

For an inclusive development policy, the development of tribal community is the major agenda which has to be adopted. We can make sure of the development of tribal community only through education. Most of the tribal community people are traditionally living in remote

areas, mostly inside forests. In my constituency also, there is a Panchayat called Edamalakudy, which is situated 30 kilometres away from Munnar and is inside Eravikulam National Park. Road connectivity is very less. Now only that kind of development is coming. The school facilities are very less. That is why, I personally took initiative and I channelized CSR fund through Cochin Shipyard. Now, a new school building is going to be constructed and there will be full-fledged facilities for schooling.

Sir, we noticed that after schooling, the tribal people are not willing to join college education also. In my constituency, in my district, comparatively there is more tribal population in Kerala. We only have one Eklavya Model Residential School. We want more such schools, not only in Idukki but also in the nearby district Ernakulam. At Kuttanpuzha also another school is needed.

After school education, most of the tribal students are not interested to join colleges. They cannot continue their studies in colleges and universities due to their own valid reasons. Sometimes SC or ST students are discriminated in the premier universities of our country. The unfortunate suicide by Rohith Vemula should not be forgotten. It is a matter of shame that a lot of tribal students are made to drop out from our top universities due to discrimination and hostility. The Government should carefully manage and stop dropout of our students.

The tribal culture has literally saved millions of lives in our country. The story of Padmashri Lakshmikutty Amma, the noted traditional healer is a case in point. Singers like Nanjiyamma and numerous other tribal artists have contributed to the richness of our culture. We should not forget that.

Opening up the avenues of higher education to tribal population has a potential to change their lives for the better. The case of young tribal IAS officer from Kerala Ms. Sreedhanya has inspired thousands of tribal students to take up higher education and prepare for joining the highest level of Government services.

For the overall development of tribal people of the whole country, opening up of a tribal university in every State should be a priority of this Government. I appeal that a tribal university in Kerala, especially in my constituency be allocated. That will be a great achievement for tribal community of Kerala.

According to other research and other reports, we can also see that the development of tribal community through more studies and more initiatives by the Government will be welcomed. For these reasons, I welcome the amendment Act. Thank you, Sir.

***m17 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** सभापति महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2023 पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, संशोधन मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसकी स्थापना होने से प्रादेशिक आकांक्षाएं पूरी होंगी। वहां पर जनजातीय कला, संस्कृति, परम्पराओं तथा जनजातीय शिक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रिसर्च सुविधाओं के साथ-साथ उन्नत जानकारी को बढ़ावा देने का भी कार्य होगा। आशा है कि राज्य के साथ-साथ पूरे देश के जनजाति समुदाय को इसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं अपने बिहार राज्य में वर्तमान में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009 और वर्ष 2016 में एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह काम स्वागत योग्य था। किन्तु वहां पर राजनीतिक लोगों को कुलपति बनाकर विश्वविद्यालय को राजनीतिमय करने का काम किया जा रहा है। यह सर्वथा उचित नहीं है। गया और मोतिहारी में स्थापित दोनों केन्द्रीय विश्वविद्यालय अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाए हैं। वहां पर अध्यापक और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अत: इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, ज्ञान की नगरी, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, वह वर्ष 2010 में माननीय मुख्य मंत्री जी नीतीश कुमार जी के अथक प्रयासों से स्थापित हुआ। यह एक मात्र आवासीय विश्वविद्यालय

है, जहां बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन की खोज की पढ़ाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था है।

सभापति महोदय, यहां की बिल्डिंग काफी बड़ी है। मैं समझता हूँ कि वहां पर जो पढ़ाई हो रही है, उसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी वहां पर उप राष्ट्रपति महोदय गए थे, हम भी गए थे। वहां पर स्थानीय लोगों ने, वहां के लेक्चरर ने, सभी ने इस बात को रखा था कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, उनके अनुसार उतने विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हमें उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप नालंदा विश्वविद्यालय पर जरूर ध्यान दें।

16.00 hrs

जब माननीय प्रधान मंत्री जी पटना गए थे तब उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग रखी थी। यह पूरे बिहारवासियों की डिमांड है। जब बिहार, ओडिशा और झारखंड साथ में थे, उस समय वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय था। यह बहुत ही पुराना है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m18 SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH):** Thank you, hon. Chairperson, Sir.

First of all, I heartily welcome this Bill. This is one of the best opportunities given to the tribal community. While welcoming this Bill, I would like to iterate some poetic statements made by Mahatma Phule, which is in Marathi language. And I quote:

"Vidyevina mati geli,

Mativina niti geli,

Nitivina gati geli,

Gativina vitta gele,

Vittavina shudra khachale,

Itke anarth eka avidyene kele."

This is in Marathi language. It means that if education is not there, you will lose everything. You will lose thinking. And you will lose everything in life. So, education is the most important thing. Our young leader, Shri Aditya Thakre once gave an example of the British Prime Minister. He said that while addressing in the UK Parliament, the Prime Minister of UK was asked as to what were his priorities, and the Prime Minister said, ? Education, education and education?. So, that is what is the priority of that country. But culture and priority are being mixed right now, and we are having serious problems with regard to the same.

The Central Universities (Amendment) Bill proposes to establish Sammakka Sarakka Central Tribal University in the Mulugu District of Telangana. I really appreciate this step for the tribal people. But this is rather delayed. You must be aware of the same also. In 2014, when the State of Andhra Pradesh was reorganised, and it was your commitment that you will do this. But anyhow, better late than never. You are doing it right now. This is a welcome act. But at the same time, the University is named under the names of Goddesses ? Sammakka Sarakka?. What does it mean? It means courage and sacrifice. Now, both the things are required while imparting education. Who is showing courage and doing sacrifice? These are the moral things. We have to set an example. Charity begins at home. The political arena right now is showing that we are not ready to sacrifice anything. We do not want to show the courage to fight against all the odds. And that is what is education. The universities are being established.

Dharmendra Pradhan ji, I would like to request one thing. What is the resource for higher education? I think an hon. Member has said that he has been saying this for the last ten years that there has been discrimination and disparity in every State, which you have also mentioned. Disparity is by virtue of the schools where they are situated. You have a single teacher school where you do not have teachers to go there. Discrimination is by virtue of curriculum and syllabus. So, the student who is going to a university is discriminated by virtue of a syllabus. When Javadekar was there, I insisted him this for a long time. I said that, at least, let it be in any language. But the syllabus for, at least, two or three subjects

like science, maths, and English should be uniform because these are the subjects which are required for clearing Joint Entrance Examinations. You have SSC Board, ICSE Board, CBSE Board, International Board, etc. I am talking about the primary education. That is not healthy. How can you expect a child to go to the university and show that he has talent? But these universities are going to provide other things also -- cultural activities, art and culture, tribal art, etc. You have provided a substantial fund also for that. I have just quoted Mahatma Phule?s poetic words. Who did it?

In Maharashtra, Karmaveer Bhaurao Patil, Prabodhankar Thakre, Shahu Maharaj ji inspired the people for education, they inspired the people to come for education. We also tried it. In Maharashtra, we tried it to give basic education by asking them to come to the class.

Dharmendra Ji, you have been called for something.

HON. CHAIRPERSON: Sawant Ji, you please address the Chair.

SHRI ARVIND SAWANT: Sir, he is my good friend.

HON. CHAIRPERSON: You can address him through the Chair.

SHRI ARVIND SAWANT: You have to see the potential of tribal people. Tribal people are very good in sports. They are very good in running and aiming. These universities should have multiple things and not that they confine to academic one. You have said that vocational and skill development also will be given to them. But then, this university has to be there where all these things are included in it. Some hostels should also be given to them. Why do these children drop out of the university? Why do these students from the Scheduled Castes or from the Scheduled Tribe communities drop out when they go to IITs and IIMs? It is because there is discrimination in basic education. They fear whether they will be able to complete it or not. Even after that, some bold steps have been taken by the Government and I feel you have launched it right now. Tribal art, traditional knowledge

system and culture will be priority of the university. It will give a chance for the children to expose their potential and vocational and skill development will also be given.

Once again, I welcome this Bill but I would like to emphasise that unless you remove the discrimination in the curriculum of the primary education, you will not get the children updated and up to the mark to cope up with the studies in the university.

Thank you so much. Once again, I support the Bill, Sir.

***m19 DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI):** Hon. Chairman, Sir, I rise to support and welcome the Central Universities Amendment Bill, 2023. On behalf of *Thalapathy* Shri M.K. Stalin who is at the helm of affairs of Dravidian Model of Government which upholds education and medicine as its two eyes, I wholeheartedly support the Bill aimed to provide a Tribal University in Telangana. Education is an asset for us which is not detachable. The vision of *Thanthai* Periyar, *Perarignar* Anna and Dr *Kalaignar* was to provide education, that too quality education to everyone in the society and on their footsteps presently the Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Thalapathy* Shri M.K. Stalin is heading a Dravidian Model of Government providing good governance to the people of Tamil Nadu. Shri M.K. Stalin has introduced a scheme to provide breakfast to children in elementary schools aimed to provide quality education. Our Leader is making Tamil Nadu a pioneer in education particularly in women?s education by providing Rs. 1000 per month to girl student pursuing higher education in Tamil Nadu. On behalf of our leader, we welcome the move to start new Universities in India. Our request to you is that not only the number of universities should increase but also the quality of higher education in these Universities should also drastically improve. Although there are more than 1100 Universities in India, only 300 Indian Universities are able to provide education of world standard. I should say it is the right time to assess and analyse our standard of education. Similarly, the Gross Enrolment Ratio as regards higher education in India stands at 27 per cent. At the same

time, this Gross Enrolment Ratio for higher education is more than 47 per cent in Tamil Nadu. This is due to the efforts of Dravidian Model of Government in Tamil Nadu giving importance to higher education starting from elementary level. Along with the basic needs such as food, shelter to live and dresses to wear, education also plays a major role in development.

I wish to state with pride that due to the unwavering efforts of the Dravidian Model of Government in Tamil Nadu, the Gross Enrolment Ratio of higher education is more than 47 per cent making it a progressive State in imparting quality education in India. During the last 5 years, almost 19000 students belonging to SC, ST and OBC communities have become dropouts making them unable to continue their studies in the Central Universities. Out of that, 2622 students are ST students. More than 35 students have ended their lives. In Tamil Nadu, particularly in IIT Chennai, many such incidents of students committing suicides have taken place due to caste discrimination shown by the Professors working there. We have raised this issue several times in this House but no action has been taken against the erring teachers. I once again want to flag this issue here. Everyone should come together to work hard to provide quality education to everyone. I wish to make an important demand that education should be taken out of the Union List and kept only in the State List. Only then education can be provided to all communities of the society including SCs, STs and OBCs. Due to NEET, more than 40 students have committed suicide in Tamil Nadu. This is not only an issue pertinent to Tamil Nadu. In Kota district of Rajasthan, more than 20 students have committed suicide opposing NEET. These students belong to SC, ST and OBC communities. When these students want to pursue higher education, such entrance exams conducted to test their ability stop them from pursuing higher studies as they create depression in them and lead them to commit suicide. Entrance exams like NEET should be stopped and banned. Only then we can save the precious lives of our students and ensure that the students belonging to SC, ST and OBC communities pursue higher education. With this I conclude by supporting the Bill. Thank you.

***m20 DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL):** Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Central Universities (Amendment) Bill, 2023. On behalf of YSRCP, I support the Bill.

The Bill proposes to establish Sammakka Sarakka Central Tribal University in Telangana by amending the Central Universities Act of 2009. Crores of people revere Goddess Sammakka Sarakka and this gesture will respect local sentiments.

Sammakka Sarakka is Goddess of courage and sacrifice and this will hopefully empower ST population. Their literacy rate as of now is 59 per cent, whereas the national literacy average is 73 per cent. I hope that such bills will empower ST population.

Sir, I take this opportunity to highlight certain issues plaguing Indian higher education system. As per all-India survey on higher education, gross enrolment ratio in higher education is 27 per cent. It is very low when compared to global average of 40 per cent. At the same time, paradoxically, lakhs of our children are pursing higher education in foreign universities. This may be called as brain drain and economic drain.

There are regional imbalances in location of premier institutions. Concentration of premier institutions in urban areas exacerbates this regional divide. There is deficiency of experienced faculty in higher educational institutions. The ratio of pupil and teacher is nearly 30 per cent whereas in USA, it is 12.5 per cent and 19.5 per cent in China and Brazil.

There is a huge skill gap between teachers and students of rural background. A bridge course may be added in the curriculum to help the rural students. Insufficient research and development fund is taking us backwards. Our investment in R and D is very meagre. It is only 0.6 per cent of GDP whereas it is 2.5 per cent in USA and 2 per cent in China.

The quality of Indian education also needs improvement. Rote learning phenomenon of India is worrisome. This impedes critical thinking and creativity. Question pattern and examination pattern should be revamped. Outdated curriculum creates substantial gap

between needs of industry and job seekers. This limits creativity and innovation. This decreases the employability of graduates. So, curriculum should be updated as per the need of industry.

Every year, nearly 10 lakh youths are coming out of colleges but industry is in search of good workers. This paradox is because of questionable quality of our education. Both, teachers and students, should be given industrial exposure. Less than 25 per cent of the total institutions of India have NAAC accreditation and only 30 per cent of universities and 45 per cent of colleges have reached ?A? level.

Sir, we have a few suggestions for the hon. Minister of Education. The financial aid in the form of scholarship, grants, and low-rate interest loans may be provided to the deprived students. Support systems like mentorship programmes, counselling services, and targeted assistance to downtrodden communities are needed. The budgetary allocation should also be increased. India is allocating around 2.9 per cent of the Budget whereas countries like USA and China have allocated around 6 per cent. Training of teachers is very crucial for quality outcomes. Incentives may be given to the teachers to boost their morale. Likewise, research and innovation need to be promoted. In the same way, collaboration between the universities and private sector is the need of the hour.

In conclusion, I would like to further put a few facts before this august House. India ranks 33rd in the world with regard to quality of education. We know that education is the most powerful weapon to change the world and it is a fundamental catalyst for growth. Around 140 crore Indians are eagerly waiting to be called *vishwaguru*. The historical Nalanda University attracted thousands of students from all over the globe. Such good days should come back to India because we are the most populous country of the world. India is blessed with a demographic dividend of having a young population. This can become a demographic time bomb if we do not provide facilities to our educational institutions and increase the employability of our graduates. Today, thousands of our children are migrating to foreign universities. This trend should be reversed. We hope that under the able

leadership of living legends like hon. CM, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy ji and hon. PM, Shri Narendra Modi ji, India will achieve this in the near future. Sir, it is sad to note that ours is a labour-driven economy. Let us make this a knowledge-driven economy. We have very few world patents. This is a testimony to this fact.

The Government of Andhra Pradesh under the able leadership of Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, Sir, has allocated Rs. 20,000 crore for setting up Amma Vodi Scheme and Rs. 4000 crore for renovation of schools and colleges under the Nadu Nedu Scheme. These schemes may be replicated at the national level.

Sir, establishing a tribal university in Telangana honours the Thirteenth Schedule of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Likewise, there are many unkept promises with regard to Andhra Pradesh. I, once again, request the Government of India to honour the AP Reorganisation Act, 2014 once again and keep the promises made in favour of Andhra Pradesh.

With these words, our party YSRCP supports the Bill. Thank you.

***m21 श्री गिरीश चन्द्र (नगीना):** महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, किसी भी देश की तरक्की की नींव उस देश की शिक्षा पर निर्भर करती है। हमें खुशी है कि यह सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना में आदिवासी वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

महोदय, हमारे देश में पिछले 68-70 वर्षों से बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान में दी गई आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गयी है व मौजूदा सरकार से जो उम्मीद थी, वह भी पूरी नहीं हो पायी। पिछले 68-70 सालों को देखें तो जो

भी सरकार सत्ता में रही, वह हमेशा आरक्षण को लागू करने की बात करती रही, लेकिन आरक्षण को लागू करने का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया है।

महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नहीं मिल रहे संविधान सम्मत आरक्षण की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

महोदय, देश में जितने भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं, वहाँ आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं लागू होने के कारण अलग-अलग विभागों/विषयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी से आने वाले प्राचार्य, शिक्षक, प्रोफेसर आदि की भारी कमी है। यदि किसी विशेष विषय में प्रोफेसर/शिक्षक की नियुक्ति करनी हो तो बड़े ही शातिराना अंदाज में मात्र एक-एक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराकर एक विशेष वर्ग के लोगों को नियुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

सभापति जी, यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि समग्र नियुक्तियां एक साथ प्रकाशित की जाती हैं तो आरक्षण की सुविधा देना अनिवार्य है, लेकिन एक पद के लिए आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार विगत सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार की मंशा आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ धोखा ही है। यदि वास्तव में वर्तमान सरकार इन वर्गों की हितैषी है तो देश भर में हो रही इस गंभीर अनियमितता को मन से दूर करने का काम करे। वर्तमान समय में छात्रों की फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखे जिससे इन वर्गों के छात्र-छात्राएं अधिक से अधिक शिक्षित हों और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

महोदय, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग एक साल से अधिक समय से वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिससे वहां के छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार से मेरी मांग है कि जिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं या खाली पड़ी हुई हैं वहां यथाशीघ्र वाइस चांसलर की नियुक्तियां की जाएं। इसके साथ ही मैं आपसे यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से सन् 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के रहते हुए जीरो बैलेंस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को चाहे एमटेक हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, बीटीसी हो या बीएड हो, सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जीरो बैलेंस पर गरीब छात्रों का एडमिशन करवा कर आगे बढ़ाने का मौका देने का काम किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप भी एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो विश्वविद्यालय आप खोलने जा रहे हैं, इसमें पिछड़े, दलित, कमजोर बच्चों को निशुल्क शिक्षा देकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

***m22 DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ):** Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.

I support the establishment of Central Tribal University in Telangana. It is a very good step for the tribals in India. But at the same time, I am concerned about what is happening to education in India. कई सालों से, खास कर जब यूपीए की सरकार थी तो जीडीपी 3 परसेंट से 6 परसेंट बढ़ाने की बात थी लेकिन देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे यह परसेंटेज कम होती जा रही है। खास कर जो यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, यदि हम किशनगंज की बात करें तो पिछले साढ़े चार साल से माननीय मंत्री जी से और बाकी रिलेटिड मंत्रालय जैसे फाइनेंस, माइनोरिटी मंत्रालयों से मिलकर भी, लिखकर भी और संसद में भी हमने कई बार कहा कि भारत सरकार की तरफ से जो 136 करोड़ रुपये एलोकेट किये गये थे, उनमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपये ही एलोकेट किए गए। हम स्वागत करते हैं कि आप नई-नई यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं लेकिन जो पहले से खुली हुई हैं, उनके लिए आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? एएमयू ने 352 करोड़ रुपये क्लासेज और बिल्डिंग के लिए एडिशनल मांगे, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा जो यूजीसी सैंक्शंड 29 टीचिंग, 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की जो जरूरत है, मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में दिया गया है, वह भी किशनगंज में नहीं दिया गया है। एक तरफ तो आप नई यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें बंद करने की कोशिश में हैं। ऐसा क्यों है? जैसा कि हमारे बिहार के साथी ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। मैं उनका समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि उसे भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी किया जाए और जो भेदभाव एएमयू से किया जा रहा है या जामिया से, उसके एलोकेशन को कम करके, यह बंद होना चाहिए। जिस तरह जेएनयू और बीएचयू का एलोकेशन बढ़ाया गया है, उसी के आधार पर एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जहां के भी हों, उन्हें अच्छी सुविधा मिले ताकि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में उनका भी सहयोग रहे और हिंदुस्तान आगे बढ़े।

सर, जैसा कि बीजेपी के हमारे साथी रूडी साहब ने कहा कि बिहार वह बिहार है, जहां के नालन्दा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। हम सब उसके बारे में जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बिहार के ज्यादातर स्टूडेंट्स को कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्वालिटी-ऑफ-एजुकेशन की कमी की वज़ह से बिहार छोड़ कर अलग-अलग राज्यों में जाकर तालीम हासिल करनी पड़ती है।

I would like to request the hon. Minister, through you, Sir, that education in Bihar should be taken very seriously. Bihar lacks medical colleges. यहां पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी बैठे हैं।

इसके अलावा, बिहार में आई.आई.टी. नहीं है, आई.टी.आईज़. नहीं हैं। इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। हिन्दुस्तान की कुल आबादी का दसवां भाग बिहार में है। यहां पर ऑपॉर्च्यूनिटीज़ नहीं होने के कारण, जैसा कि बीजेपी के हमारे साथी ने कहा कि हमारे बिहार के लगभग चार करोड़ लोग हिन्दुस्तान के अलग-अलग कोने में काम करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही दर्दनाक हादसे के बारे में भी बताया कि बेंगलुरु में एक जगह बिहार के सात मजदूर मारे गए। इसी तरह, हर महीने कहीं न कहीं हमारे मजदूर मारे जाते हैं, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी गुजारिश होगी कि किशनगंज ए.एम.यू. सेन्टर पर ध्यान दें।

सर, आपने भी मुझे देखा होगा कि बैनर लेकर पिछले साढ़े चार सालों से लगातार मैं गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़ा हूं। लोगों की जो जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करें। हमारा जो हक़ है, वह हमें मिले। हमें टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ मिले। जो एलोकेटेड फंड्स हैं और हमारी जो डिमांड है, वह हमें मिले।

***m23 श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन):** माननीय सभापति जी, तेलंगाना राज्य में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित इस संशोधन विधेयक पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

<u>16.27 hrs</u> (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

महोदय, सबसे पहले, मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का और हमारे एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय धर्मेन्द्र प्रधान जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वे एक महत्वपूर्ण विधेयक लाये हैं। यह पूरा विधेयक जनजातीय समाज के हमारे बालक-बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान के लिए है। आज मैं देश के 11 करोड़ जनजातीय बंधुओं की तरफ से भी देश के प्रधान मंत्री के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज को एक गौरव प्रदान किया है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से 15 नवम्बर को ?जनजातीय गौरव दिवस? की घोषणा करने का काम भी देश की सरकार और देश के प्रधान मंत्री जी ने किया है।

महोदय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे जो हेतु है, उसमें सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री जी का मूल मंत्र ?सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास? है। इस शब्द के साथ जनजातीय

समुदाय का जो विश्वास देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति है और इस समाज को जोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी को लेकर तेलंगाना में यह केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

हमारा जो आदिवासी समुदाय है, उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों और पहाड़ों में रहने वाला समुदाय, जिन्हें शिक्षा के नाम पर कोई भी चीज प्राप्त नहीं थी, ऐसे तमाम प्रकार के जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2014 से लेकर अभी तक प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तरक्की हुई है। देश के अनेक प्रकार के हमारे जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है।

महोदय, इस विधेयक के अन्तर्गत, नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत भी हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हुआ है। पहाड़ पर रहने वाला हमारा जो समुदाय है, वह शिक्षा के लिए तरसता है। वह वहां पर मजदूरी करता है। तेलंगाना जैसा प्रदेश, जहां हमारा आदिवासी समुदाय निवास करता है, वह शिक्षा की उन्नति के प्रयास में आगे बढ़े।

हमारे जनजातीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, जिसके मुखिया आदरणीय शिवराज जी हैं, वहां पर अमरकंटक एक स्थान है, जहां पर माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है।

मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम से एक स्थान है, जहां पर माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, उस अमरकंटक में भी एक जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वहां पर हमारे आदिवासी बच्चों की उन्नत शिक्षा की पहल की शुरूआत हुई है। वहीं पर मध्य प्रदेश में ऐसे शोध केंद्र स्थापित हुए हैं। जिस प्रकार से तेलंगाना की धरती पर यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, इसमें हमारे आदिवासी बच्चों हायर एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा मिलेगी। वे चित्रकला भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। उनकी बहुत सारी पुरानी कला पद्धति है। हमारी नृत्य कलाएं हैं, वहां पर उनका भी अध्ययन किया जाएगा। आज भी देश भर में देखा जाए तो सबसे अच्छी कला पूरे देश भर में आदिवासी समुदाय की रहती है। कला और संस्कृति के साथ हमारे आदिवासी समुदाय की जो पूजा पद्धति है, जो रीति-रिवाज़ हैं, जो अन्य समाज के वर्ग भी देखते हैं कि किस प्रकार की पूजा पद्धति यह समुदाय करता है, इस विश्वविद्यालय में उसका भी अध्ययन कराया जाएगा। मुझे लगता है कि यह देश के जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात भी है कि हमारी संस्कृति, कला, हमारी पुरानी परंपराएं, पूजा पद्धति, हम प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार से पूजा पद्धति करते हैं, उसका अध्ययन करने का भी यह शोध केंद्र कहलाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूँ कि हमारी पुरानी परंपराओं का भी अध्ययन कराया जाए।

मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय का नाम हमारी जनजातीय माता के नाम पर, सम्मक्का सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा। इस विश्वविद्यालय के कारण हमारे तेलंगाना के कई जनजातीय बंधुओं को शिक्षा में लाभ भी मिलेगा। मैं इस बात का विश्वास भी व्यक्त करता हूँ कि पूरे देश में 2014 से ले कर अभी तक जनजातीय समुदाय ने ग्रामीण क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वविद्यालय हमारे जनजातीय बंधुओं के पढ़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। मैं आज इस सदन में हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

***m24 श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती):** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, इस बिल का मूल उद्देश्य तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। हम अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का स्वागत करते हैं। सरकार का प्रयास आदिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा।

महोदय, तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना के साथ ही इस विश्वविद्यालय के निर्माण में पर्याप्त बजट जारी करना चाहिए, जिससे इस विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य निश्चित समय में पूर्ण किया जा सके। यह विधेयक प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

महोदय, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कला, संस्कृति और रीति-रिवाज़ों में शिक्षण और अनुसंधान प्रदान कर उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना अनिवार्य है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही, पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्री शिक्षा व्यवस्था को भी लागू किया जाए। भारत सरकार और शिक्षा मंत्री जी से यह मेरी विशेष रूप से मांग है। अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगी तो देश आगे बढ़ेगा । धन्यवाद।

***m25 श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग):** सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर, यह सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अपने आप में हमारे जनजातीय समाज, आदिवासी समाज और देश के लिए गौरव का क्षण है। हमारे मोदी जी और उनकी सरकार ने एक बार फिर से अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट किया है। हम बार-बार कहते हैं कि हमारी यह सरकार आदिवासी, जनजाति, महिला, गरीब और हमारे युवा साथियों के प्रति समर्पित है। यह भाव एक बार फिर से हम सबको यहां देखने को मिलता है। आँकड़े भी इसी चीज की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वैसे तो कल से लेकर आज तक हमारे बंगाल के बहुत सारे सांसद जोर-जोर से बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा और आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा। साढ़े नौ साल से मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षण इसके लिए कोशिश हुई है। आजादी के बाद इतने सालों तक इतनी सरकारें रही हैं, प्रमुखता से कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग पिछड़ गए थे। उनको आगे बढ़ाना हमारी सरकार का एकमात्र ध्येय था, इसलिए मैं पूरी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं।

सर, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के विषय के बारे में थोड़ा रखना चाहूंगा। पूरा नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई-डूवर्स का इलाका है। वहां पर बहुत सारे हमारे जनजाति और आदिवासी समाज का घर है। नॉर्थ बंगाल के अंदर, विशेषकर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा इलाके आते हैं। हमारे क्षेत्र की करीब तीन करोड़ के आसपास आबादी है। यहां के चाय बागान और सिनकोना बागान में हमारी श्रमिक माताएं काम करती हैं। उनमें ज्यादातर महिलाएं रहती हैं। चाय बागान में करीब 6000 रुपये उनके महीने की कमाई रहती है। उनको बहुत तकलीफ में अपने जीवन को जीना पड़ता है। उनको अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, दार्जिलिंग में एक हिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। ऐसी माँग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसका कारण भी है। देखिए, बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है और कोलकाता से नॉर्थ बंगाल बहुत दूर पड़ता है। बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, उसने हमेशा नॉर्थ बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वहां पर एक एम्स अस्पताल बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी हो गई थी और वह नॉर्थ बंगाल में बनना था, लेकिन बाद में टीएमसी सरकार उसको भी साउथ बंगाल ले गई। इस प्रकार नॉर्थ बंगाल कई सारे मायने में पिछड़ा है। हमारे पास क्षमताएं बहुत थीं। क्षमताएं होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा है। इसीलिए, मैं आपके माध्यम से यह मांग रखना चाहता हूं कि वहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाए।

सर, दार्जिलिंग की एक विशेषता रही है। दार्जिलिंग में सिर्फ बंगाल या आसपास के ही नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बच्चे भी आकर शिक्षा लेते रहे हैं। हमारे पड़ोस के जो मुल्क हैं, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या भूटान हो, राजशाही परिवार के बहुत सारे लोगों ने दार्जिलिंग में आकर शिक्षा ग्रहण की है। अगर हम दार्जिलिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए हमारे पास जमीन भी है और स्ट्रटेजिक लोकेशन भी है। अभी बंगाल सरकार ने कोशिश की थी कि एक हिल यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग में बनायी जाए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह सिर्फ कागज़ों में ही बनी है।

फिजिकली आज तक उसकी न कोई बिल्डिंग है, न वहां कोई वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ है। ?(व्यवधान) यह मंकू में है। देखिए, हमारे टीएमसी के सांसद को पता भी नहीं है कि इन्होंने घोषणा की है। इनकी घोषणायें सिर्फ कागजों में रह गई हैं। कुछ बच्चों ने वहां पर एडमीशन लिया था। आज तक उनकी फिजिकल क्लास नहीं हुई। उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है। बंगाल में टीएमसी सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया है। हमारी सारी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि दार्जिलिंग हमेशा एजुकेशन हब था। अगर हायर एजुकेशन फैसिलिटी वहां बन जाती है तो वह उस क्षेत्र के लिए, पश्चिम बंगाल और पूरे देश के लिए बड़ा गर्व का विषय रहेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m26 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Thank you very much, Mr. Chairman, Sir, for giving me this chance to take part in the discussion on a very important Bill, namely, the Central University (Amendment) Bill, 2023.

I rise to fully support the Central University (Amendment) Bill, 2023 providing for setting up Sammakka Sarakka Central Tribal University in the State of Telangana. This is to be appreciated in two ways. Firstly, it is honouring the commitment made by the Andhra Pradesh State Reorganisation Act in the year 2014 for which we have witnessed a series of agitations in this House. One of the demands of that State is being fulfilled. In that way it is to be appreciated. Secondly, according to me this is a very good move because it will achieve the goal of social justice, that too among the tribal population in the country. The tribal population is a marginalised section of the society and is a suffering community. They

have been deprived of the basic human rights since long. After Independence, we have been trying our level best to put them in the mainstream of our country. But even after 75 years of our independence we are not able to bring them into the mainstream because of so many reasons. I am not going into all the reasons because of which for ages the tribal population is deprived. The basic reason is that access to higher education or access to quality education is not there. We all know that education is the strongest weapon in the world to transform a society. Here, as far as the tribal population is concerned, access to quality education is very, very remote. That is the basic reason why the tribal population of our country is not able to uplift themselves.

As far as this Bill is concerned, this will definitely be providing an opportunity to have access to quality higher education in the Central University in the State of Telangana, and that too exclusively for the tribal population. Therefore, this has to be appreciated. Why it is being established only in the State of Telangana is also justified. The literacy rate in the tribal population is very low when compared to the national average. The national average literacy rate is 73 per cent. But unfortunately, as far as the tribal population is concerned, this is only 59 per cent. If you see the gross enrolment ratio, the national average is 18.9 per cent but in Telangana it is only 7.8 per cent. So, a Central Tribal University in the State of Telangana is well justified. It is not only providing an avenue for the educational opportunities but it is also promoting economic empowerment of the marginalised section of the society, that is, the tribal population. Therefore, I fully agree, appreciate, and support the Central University (Amendment) Bill providing for a Central University exclusively for the tribal population.

I would like to seek certain clarifications from the Minister and the Government. Since this is exclusively for the tribal population, I would like to know what would be the mode of admission for this University. Also, regarding the curriculum, what are the courses to be offered? What is the curriculum of this University? A detailed explanation is required on this. Also, the mode of admission has to be explained. Most of the hon. Members in this House

during the interventions have expressed their concerns regarding the quality of our higher education.

I would also like to stress on it. Prof. Saugata Ray ji has also mentioned that point. We are celebrating the *Amrit Kaal Mahotsav.* At this time we are having 56 Central Universities and more than 1,000 Universities. But even after 75 years of our Independence, we are not able to have a single university within the list of 200 universities having international or global standards. What is the reason for it? Why is it so? This issue has to be taken care.

We all have been demanding since long for having not less than six per cent of the GDP to be spent or allocated for education purposes. But unfortunately, as was just now stated, year after year the allocation or contribution for education is getting diminished in one way or the other. So, not less than six per cent of the GDP has to be spent for education and that too in particular for higher education.

The quality of education is very low. What societal impact is there? A big impact is there. In my State also it is well known to me that after Class 12 almost all the students are going for higher education to Europe, Canada, UK, US, Ireland and many other countries. Nowadays, the young and adolescent people are missing from our State. A statistical report about the State of Kerala has proved that by 2030 the State of Kerala will be an old-age home because students will not be there, and young and adolescent population will be missing from there. It is because we are not able to provide quality education in our country.

Some of the state governments are taking it as an achievement that they are able to provide foreign education for this much number of students. One thing has to be kept in mind that those students who are migrating from India to Canada, Europe, US, UK and all these countries are not coming back. They will get the citizenship there and they will stay there only. It means that the brain drain is happening in a big way. So, that issue has to be addressed. How do we address it? We have to improve the quality of higher education in our State. This is the way by which we can address the issue of migration.

At the time when this Government came to power in 2014, so many programmes and projects were announced like the Government is going to have tie-ups with foreign universities and have better higher quality education in our country so that our student community will get better education of international standards. But unfortunately, even after nine-and-a-half years or even after conclusion of the 10th year of this Government, are we able to achieve that standard of higher education in our country? The answer is No.

There was another argument that since these are public institutions and they are under the Government, we are not able to have good standard of education. We have privatised higher education. Not only higher education, but the entire education system is privatised. The commercialisation of education is going on. But even after indiscriminate and rampant privatisation of education we are not able to have international standard of education in our educational institutions. This means that we have to think about it in a threadbare manner so as to improve the quality of education in our country.

What is the main reason for it? I will conclude after mentioning the main reason. One of the main reasons for the low quality of education is politicising the educational system in our country. Sir, you are well aware about the universities. You also spoke today morning during the ?*Zero Hour*? submission about politicisation of universities. In the State of Kerala there is Governor *v/s*. the state government going on in the education sector. There is no Vice-Chancellor in nine universities for the last two years, and in-charge Vice-Chancellors will be provided and the Party-political administration is going on. So, the highest form of politicisation of the education system is taking place. The University Grants Commission has issued a Circular. Yesterday, a question was asked by Shrimati Supriya Sule ji and the Minister has also admitted that a direction has been given to all the universities by way of a Circular that a ?selfie point? has to be installed in all the university campuses with the background of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. If this will happen in the country, then definitely all the Chief Ministers in the State will also issue Circulars that in all the public educational institutions as well as in all the colleges and schools a selfie point of

the Chief Minister has to be installed so as to propagate the political, popular image of the Chief Minister and the political leadership in our country.

As far as the education system is concerned, this is absolute politicisation of education which is the main reason for the lowering of standard of education in our country. Just like the Scheduled Tribes in our country, one of the marginalised communities is the coastal and marine fishermen community in our country. We have a big coastline and their standard of living is very poor. So, I would like to urge upon the Government to have a Central Marine University to give preferential treatment to the fishermen community, and it would be better if you established it in the State of Kerala which has a coastline of more than 600 kms.

***m27 SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM):** Sir, the hon. Prime Minister announced in Telangana that a university in the name of Tribal Goddess, ?Sammakka and Sarakka?, would be set up in the heartland of Telangana where a large tribal population is living. It would not only cater to the tribal people of Telangana, it is also a big boon for the tribals in the country. I think the utmost priority is to be given to only tribals unlike small percentage of reservation given to them in the other institutes. They will get the top priority for tribals alone. This would pave the way for 100 per cent literacy among tribals in the country.

For the first time, we have a President of India from a tribal community and we would see many more scientists and political leaders with this great initiative of hon. Modi ji to set up Sammakka Sarakka University.

I wholeheartedly support this Bill. As it is a part of the A. P. Reorganisation Act, there are some of the issues which have to be settled as per the Act, though it is out of the subject to mention right now. I would request the Government of India to look into the issues as far as the A. P. Reorganisation Act is concerned. Thank you Modi ji for giving this wonderful university to Telangana.

***m28 डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से इस सदन में सैल्फी प्वाइंट का और माननीय प्रधान मंत्री जी का डिसकशन चल रही है। मुझे निराशा होती है कि यह देश कैसा हो गया? हम किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं? पहली बार सुनने को मिल रहा है कि प्रधान मंत्री किसी पोलिटिकल पार्टी का आदमी है और यदि कोई उनके साथ सैल्फी ले लेगा, उनकी फोटो के साथ सैल्फी ले लेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। इस देश की इसी मानसिकता ने देश को गुलाम रखा। हम सबने बचपन में बाबर के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा, गजनी के बारे में पढ़ा और गौरी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने हमारी बहू-बेटियों की इज्जत ली, उनको ग्रेट किंग के तौर पर पढ़ने और बोलने में किसी बच्चे का दिमाग खराब नहीं होता, लेकिन यदि वह माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। क्या हम इसी मानसिकता के साथ पार्लियामेंट में आए हैं?

महोदय, बिरसा मुंडा जी ट्राइबल्स के भगवान हैं।

आजादी के आंदोलन में बिरसा मुंडा जी ने बहुत बड़ा काम किया। 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। पूरा का पूरा आदिवासी समाज कांग्रेस को मदद करता रहा, सपोर्ट करता रहा। क्या आपने कभी भी 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया? हम 15 सालों से यहां पार्लियामेंट में हैं। वर्ष 2014 के बाद की सिचुएशन अलग है। रूडी जी तो मुझसे पहले आ गए थे। क्या इससे पहले किसी को पता है कि इस संसद भवन में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगी हुई है? क्या किसी ने बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर कभी माल्यार्पण किया है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हम तो करते ही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वहां प्रधान मंत्री जन-मन कार्यक्रम चालू किया और उसी का यह नतीजा है। जब पार्लियामेंट में कोई कमिटमेंट होता है, तो वह कमिटमेंट पूरा करने का काम सक्सेसिव गवर्नमेंट का होता है। माननीय प्रधान मंत्री जी हमेशा डेमोक्रेसी में बिलीव करते हुए सोचते हैं कि जो भी कमिटमेंट हुआ है, वह पूरा हो। वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2023 में हम इस बिल को लेकर आए हैं। क्या कभी इसके बारे में सोचा है कि 9 साल कैसे लग गए?

महोदय, मैंने कई लोगों को देखा कि इलेक्शन का समय था, तो आपने बोल दिया, कर दिया। इलेक्शन तो खत्म हो गए न, तेलंगाना में अब तो कोई इलेक्शन नहीं है न, इस यूनिवर्सिटी से इलेक्शन में कोई वोट नहीं मिलता न। 9 साल इसलिए लग गए, क्योंकि राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी। यदि जमीन नहीं मिलेगी, तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो या भारत की संसद बनानी हो, नहीं बन सकती है। मैं केवल दो-तीन शब्दों में अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। इस सदन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिस राज्य में पैदा हुआ, जहां मेरे पूर्वज हैं, जहां मेरे माता-

पिता रहते हैं, वह एक बड़ा राज्य है। अशोका द ग्रेट के अलावा धर्म की बात करें, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिक्खिज्म तीनों धर्म उसी बिहार से निकले हैं, लेकिन कितने लोगों ने बुद्ध की भूमि देखी है? कितने लोगों ने जैन की भूमि देखी है? कितने लोगों ने सिक्ख की भूमि देखी है? कितने लोगों ने पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना है, जो महान राजा था? अशोका डायनेस्टी के बाद जिसने इस देश को इकट्ठा किया, क्या हमने उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया है? कितने लोगों ने चोल वंश को देखा है? आप कंबोडिया, सिंगापुर, बैंकाक जाइए तो आपको चोल डायनेस्टी के बारे में विस्तार से दिखेगा, लेकिन नॉर्थ-साउथ में, पॉलिटिक्स में, हिंदू-मुस्लिम में, जैन में हमने ऐसा बांट दिया कि हमको बाबर याद आ रहा है, अकबर याद आ रहा है, लेकिन चोल डायनेस्टी नहीं याद आ रही है। पुष्यमित्र शुंग, अशोक द ग्रेट आज याद नहीं आ रहे हैं। यही एक पीड़ा है।

सर, मैं दो-तीन बातें और बोलना चाहता था। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यहां पर ड्रॉप-आउट की बहुत चर्चा हुई। जहां तक मेरी जानकारी है, ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, या तो उनकी अच्छी नौकरी लग गई है या एक कॉलेज छोड़कर वे दूसरे कॉलेज में चले गए हैं। अत: मुझे लगता है कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो ड्रॉप-आउट बच्चे हैं, वे ड्रॉप आउट होकर घर में बैठ रहे हैं या वे कहीं नौकरी पा रहे हैं, जिससे ड्रॉप-आउट का डिस्कशन खत्म हो। मैं एक छोटे-से पॉइंट के लिए खड़ा हुआ था। मेरा गांव विक्रमशिला है। रूडी जी से कल मैंने आग्रह किया था कि वह विक्रमशिला गए हैं, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बोलें। मैंने कांग्रेस के वक्ता को भी सुना। सभी कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी से बड़ा विश्वविद्यालय मेरे गांव का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। वहां जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, जो यह कहता है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी का कोर्स विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गाइड करती थी। वह ओरिजनल यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वह है, जिसने इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया। भगवान अतीश दीपांकर, जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसी साल जला। प्रेमचंद्रन जी से मुझे निराशा हुई। वह कह रहे थे कि हम दो सौ विश्वविद्यालयों में नहीं हैं। नहीं हैं, तो क्या हो गया? आज गूगल का हेड कौन है? आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है? सुंदर पिचई कौन है? सत्या नडेला कौन है? हमारे लोग देश की इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्यों परेशानी हो रही है?

<u>17.00 hrs</u>

यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ?मेक इन इंडिया? कहते हैं, वे यदि ?वोकल फॉर लोकल? की बात करते हैं तो आपको अपने ऊपर प्राइड होना चाहिए कि हमारे बच्चे यदि 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं हैं, तब भी वे आगे बढ़ रहे हैं। उस विक्रमशीला विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 415 करोड़ रुपये दिये।

सर, अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं। आज तक पिछले 9 सालों से बिहार सरकार ने वहां लैंड नहीं दी है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कीजिए। दुनिया को विक्रमशीला के बारे में बताइए कि विक्रमशीला वह विश्वविद्यालय है, जिसको वर्ष 1189 में बख्तियार खिलजी जला रहा था, वही ऐसा साल है, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी। हमारी सभ्यता, संस्कृति, विचार और विश्वविद्यालय इतने बड़े थे कि वेस्ट हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, इसीलिए विक्रमशीला विश्वविद्यालय को रीस्टोर कीजिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, Prime Minister?s selfie should not appear ? (*Interruptions*) It is not correct. ? (*Interruptions*)

***m29 SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM):** Thank you Chairperson, Sir, for giving me the opportunity to speak. First of all, on behalf of Telugu Desam Party, I would like to whole-heartedly support the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 which facilitates setting up of ?Sammakka Sarakka Central Tribal University? in the State of Telangana. Even after the bifurcation of the two States, Andhra Pradesh and Telangana, no matter how the political parties converse with each other, the people of both the States have always maintained brotherhood, have always maintained love, peace and harmony between each other. Maintaining that spirit, I would like to mention in this august House that Andhra Pradesh will be the first State which is happy when something good is happening in the State of Telangana. Considering that, bringing the Tribal University to the State of Telangana is a very happy issue for the State of Andhra Pradesh also.

Considering the tribals also, it is high time that the Government also took responsibility in giving them social, economic and political representation that is duly required for them. How do you address all these three different sectors which are very important for a community or a group? It is by providing them education. Education is the primal weapon which can give you that kind of boost which is required in the society. Definitely, this University is going to help them achieve that. On top of that, it is also important for us to study the art, literature, culture and also the customs of the tribal population. Today, when the whole world, especially the planet is looking towards the environment and climate and

also the nature, we are looking at it very, very strongly. No matter how much we say that the tribals are very innocent or tribals are very backward, we are on the verge of a revolution where we are going to adapt more and more of the customs that the tribals have been following. That revolution is definitely going to come. The Central Universities that we are talking about regarding the tribals, I think they have a very distinct and important role to play in this kind of a revolution. So, definitely studying of the art, culture and customs is also very, very important as indicated by the Bill also.

But why exactly are we discussing this Bill now? This is because of the Andhra Pradesh Reorganisation Act which dedicates two Universities, one for Telangana and one for Andhra Pradesh. We are currently discussing regarding Telangana. I would like to go into the brief history regarding the Central Tribal University for Andhra Pradesh also. When Telugu Desam Party was in power and Chandrababu Naidu was the Chief Minister in the State, from 2014 we have been strongly pursuing with the Central Government for establishing the Tribal University in the State. Also, Uttarandhra has the most tribal population in Andhra Pradesh. So, we wanted to establish it in Vizianagaram district. We have provided 525 acres. The State Government took the responsibility of building the compound wall also by spending Rs.10 crore. Then, we strongly persuaded the Central Government at that time. In 2018, the Central Government had brought the Bill also. But just because we were on the verge of elections and it was the end of the 16^{th} Lok Sabha, the Bill lapsed. But the Central Government keeping their commitment intact after coming back ? it was the Modi Government which came back at the Centre ? in July 2019, they brought back the Bill. We passed the Bill in this very House. We know that the site is also ready in Vizianagaram. But the present State Government which is there in Andhra Pradesh has a very strange way of working.

They work on political vindictiveness. Whatever the decisions were taken by the previous Government, they do not want to continue or they do not want to go forward on any of those decisions. So, just because the land was given during the TDP?s rule, they went back on the decision and they sat on the decision. They wanted to change the land. But how

much time have they taken? They have taken four years. The Bill got passed in July, 2019 in the Parliament, and the foundation stone for that University got laid in August, 2023. The hon. Minister has himself come and laid the foundation stone. If so, much of time was taken, once the Bill is passed, to lay the foundation stone only, then when are we going to see this University as a reality and when are the students actually going to see a physical campus there, and go and study there? So, this is my request to the Central Government to speed up this activity of setting up this Central Tribal University in Andhra Pradesh also. I know that this has happened because of the delay of the present Government in handing over the land. But it is a very strange behaviour that I am seeing. Usually, in these kinds of issues, the State Governments are the active pursuers. They run after the Central Government saying that as they are giving the land, why is the Central Government not setting up the University? But this time, we are seeing that the Central Government has sanctioned Rs. 823 crore and has given Rs. 400 crore for Phase-I, and the Central Government is the one which is pursuing with the State Government asking the State Government to provide land so as to set up a Tribal University for Andhra Pradesh. So, with this attitude only, please speed it up. We do not have any confidence in the State Government that they will actively pursue on this matter. Even though we are sitting in the Opposition, we want to strongly fight for the rights of Andhra Pradesh. So, please establish this University as soon as possible. According to the A.P. Reorganisation Act, we have other institutions also. We have IIM in Vishakhapatnam and IIT in Tadepalligudem. NIT is also there. In NIT, there is no dedicated Director right now. There is an in-charge Director. There are some staff deficiencies also in all these institutions. Getting the Bill passed in this House is half the job done. But when we will have the right curriculum, right staff, and when we will maintain a full-fledged infrastructure at these campuses, then only the job will be fully done. Therefore, I request the Central Government to ensure that they walk the talk and complete all these institutions in time because we are into the final year of completion of A.P. Reorganisation Act. The Act has given only ten years to complete all these things. But so many issues are pending. The Central Government has the prime responsibility in completing this. Once again, on behalf of the State, we request the Ministry of Education,

whatever comes under its ambit, to ensure that everything is completed in time and as has been decided.

Thank you very much for giving me time.

***m30 SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY):** Thank you, hon. Chairperson, Sir.

I would like to thank the Central Government for setting up a Tribal University in Telangana. It will be very helpful for the development of tribal people in the education sector. At the same time, the Central Government should assure some reservation for the tribal people of the States concerned.

Normally, the Central Universities do not have any reservation for the mother State or the concerned States. In Puducherry, there is a Central University. The Central University is the only university in Puducherry. There is no State University. At the same time, there is no reservation for the students of Puducherry, and it is attached with the Andaman and Nicobar Islands. There is no specific reservation for the students of Puducherry and Andaman and Nicobar Islands. So, the very purpose of the University is totally defeated because the local people are not being developed for this purpose. If you are setting up a Tribal University in the concerned area, then you must assure some reservation for it. You can see the example of Ladakh. They started a separate university in Ladakh. But at the same time, there is no reservation for the students of Ladakh in the University. So, it is a pathetic condition for the State concerned. Therefore, the Central Government should consider to reserve some seats. A minimum of 25 per cent of the seats have to be assured for the tribal people or the people of the State concerned.

Hon. Chairperson, Sir, through you, I would like to request the hon. Minister to consider this thing. Thank you, Sir.

***m31 श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) :** अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे आदरणीय धर्मेन्द्र प्रधान जी द्वारा प्रस्तुत किए गए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बिल के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। यहां बहुत से वक्ताओं ने बातें कही हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मेनडेट है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं केवल उन्हीं बिंदुओं तक कन्फाइन रहूंगा। मुझे लगता है कि इसके दो-तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है -Mandated by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. वर्ष 2014 का जो आन्ध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसमें इसको इस्टैब्लिश करने की बात थी तो यह हमारे लिए ऑब्लिगेटरी था।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान आर्टिकल 46 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। Article 46 of the Indian Constitution provides that the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. आर्टिकल 46 का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उस आर्टिकल 46 या हमारे आदिवासियों के लिए न केवल एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान के इन आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पीएमजनमन स्कीम शुरू की है। इसमें भारत सरकार की यूनियन कैबिनेट ने 24 हजार 104 करोड़ रुपये अप्रूव किए हैं। The PM-JANMAN is a Rs. 24,104 crore Tribal Welfare Scheme approved by the Union Cabinet. It is one of the largest Central Schemes and is targeting the largest tribal community in terms of outlay. आज आजादी के बाद देश के आदिवासियों के लिए इतने बड़े बजट का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। इसके लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किन्हीं राज्यों में रहने वाले आदिवासी हमारी सरकार और भारत के प्रधान मंत्री का निश्चित तौर से स्वागत कर रहे हैं कि आज उस क्षेत्र और उस धारा को आगे किया गया है। The scheme focuses Particularly Vulnerable Tribal Groups to address their specific needs and aims to provide various facilities including housing, drinking water, sanitation, education, health, nutrition, road and telecom connectivity and sustainable livelihood opportunities. झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, बिहार या पूरे हिन्दुस्तान के हर राज्य में जिस तरह से एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है और वे सुदूर गांव के जंगलों में रहते थे, उनके लिए न हाउसेज़ हैं, न एजुकेशन है, न्यूट्रीशन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उनके में जीवन कितनी मिलेगी।

महोदय, आज पूरे देश के उन आदिवासियों के लिए इतना बड़ा आउटले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का लाल किले से देश के लोगों को हाउसेज़ देने का संकल्प था कि जिसके सिर पर पक्की छत नहीं है, हमारी सरकार देश के गरीब, खेत-खलिहान में रहने वाले हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत देगी। आज उस कल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार ने जनमन स्कीम में यह तय किया। The scheme includes the construction of approximately 4.9 lakh *pucca* houses at a cost of Rs. 2.39 lakh per house. ये देश के उन आदिवासियों के लिए है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किए। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो चाइल्डहुड में उन आदिवासी बच्चों को उन जंगलों, घरों से निकालकर देश की मुख्य धारा में लाएंगे। हमारे रूडी साहब ने अच्छा कहा था कि शिक्षा है, उसी के नाते हम सब यहां बैठे हैं और एजुकेशन ही है, जो हमें ज्ञान देती है।

एजुकेशन ही हमको ज्ञान देता है। उसके नाते ही हमने शुरू किया कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसका ऑबजेक्ट है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, खास तौर से जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और उनको Not only to enable them to avail of reservation in high and professional education courses for jobs in public and private sectors but also to have access to the best opportunities in education at par with the non-ST population. आज यह यूनिवर्सिटी खोलने का लक्ष्य क्या है? हमारी सरकार का लक्ष्य यह है कि आज जो यह कहा जाता है कि जो नॉन एसटी पॉप्युलेशन है, जो शहर में रह रहे हैं, अभिजात लोग हैं, उनको अवसर और ऑपर्च्युनिटी मिली और वे आगे निकल गए। आज हमारी सरकार का संकल्प है कि उन लड़कों की तुलना में हमारे वे आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको भी इनके कम्पीटिशन में लाकर आगे कर सकें। यही नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को हम इस तरह से प्राप्त करेंगे कि हमारी सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तेलंगाना के ईस्टैबिलिशमेंट में है It aims to cater to the regional aspirations of the State of Telangana. हमारे एकाध मैम्बर्स ने कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है? इसमें साफ दिया गया है कि जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी, it will perform educational and other activities similar to any other central universities. मतलब, जो दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन्हीं के एटपार, उन्हीं की तरह से यह सेन्ट्रल ट्राईबल यूनिवर्सिटी भी रहेगी। क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता है? क्या आपको अपनी कांस्टीट्यूएंसी के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है? मेरे लिए देश है, लेकिन जब मैं अपने गांव में जाता हूं तो वहां की मिट्टी हमें चंदन की तरह खुशबू देती है। वहां की पगडंडियों पर सरसों के जब पीले फूल देखते हैं तो लगता है कि जैसे जिंदगी में जन्नत मिल गयी है। आज हमारे उन ट्राइबल्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी क्योंकि पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आयी तो हमारे ट्राइबल्स

के लिए एक यूनिवर्सिटी बनायी गयी, जिसमें देश भर के ट्राइबल्स के बच्चे जा सकेंगे। एक सेन्ट्रल एकलव्य यूनिवर्सिटी शुरू की गयी है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं केवल उसी विषय से रिलेटेड बोल रहा हूं। आज उनकी एक्सैस क्या होगी?

HON. CHAIRPERSON: Mr. Jagdambika Pal, please conclude now.

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक लाइन बोलकर कनक्लूड कर रहा हूं। Focusing on tribal art, tribal culture and technology aims to promote advance knowledge about tribal art, culture, customs and technological advancement for the tribal population of India. अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आधा घंटा लगेगा। माननीय धर्मेन्द्र जी इसको अपने उत्तर में बताएंगे। मेरे ये सारे विषय देश में एक रेवोल्यूशन लाएंगे। इस बिल के पास होने के बाद आदिवासी बच्चों के आर्ट में, कल्चर में, एजुकेशन में, कस्टम में, टेक्नोलॉजी इत्यादि, सारी दुनिया में उनके पंख खुलेंगे और दुनिया में आकाश की क्षितिज की ऊंचाईयों तक वे पहुंचेंगे। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

***m32 ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA):** Thank you Sir. I support the Central Universities (Amendment) Bill, 2023. For ages, the tribal population are facing significant challenges in accessing higher education.

According to the Ministry of Tribal Affairs, in 2023, the literacy rate of tribal population is notably lower than the national average, standing at 59 per cent in comparison to overall rate of 73 per cent. This educational disparity further exacerbates their struggle for higher education. The enrolment rate in higher educational institutions is disproportionately low among tribal students.

Furthermore, the gross enrolment ratio in higher education in Telangana is 7.8 per cent, which is substantially lower than the national rate of 18.9 per cent as per the all-India survey on higher education of 2020-21.

The establishment of Sammakka Sarakka Tribal University, therefore, will address the huge regional and educational gap among the tribal population of the country in general and Telangana in particular. Therefore, I support the Bill.

Sir, there is a news in today?s *Malayala Manorama*. One of the former Ministers of Karnataka, Shri Goolihatti Shekhar, belonging to ST community, has not been permitted to enter the Hedgewar Museum in Nagpur. It is reported in today?s *Malayala Manorama*. He has not been permitted to enter the Hedgewar Museum in Nagpur.

When we are talking about encouragement of the tribal students or tribal people in India, at the same time, we are facing such type of discrimination. We have to understand and address this issue.

With these few points, I am concluding my speech and supporting the Central Universities (Amendment) Bill.

Thank you.

***m33 श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर):** आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इस बिल का स्वागत करते हैं और ट्राइबल बच्चों के लिए इस व्यवस्था को देना अत्यन्त जरूरी था। इसको पिछले 10 सालों से किए गए एक वादे के दृष्टिगत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से आए सांसद आदरणीय राम नायडू जी की वर्षों से की गई यह मांग आज सकारात्मक रूप ले रही है। इसके लिए मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ।

इसके अन्दर जो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वे तीन लेवल पर आती हैं। पहली, हमारे इन नवयुवकों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल लोग पहाड़ी इलाकों में और उसके साथ-साथ वन क्षेत्रों में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों में रहकर वहां की पढ़ाई करने के बाद इनको जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स रहते हैं, भाषा को लेकर जो बैरियर्स हैं, उसमें भी बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। उनको दृष्टिगत रखते हुए इन यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर अक्सर यह पाया गया है कि जो लोकल टीचर्स होते हैं, जो उनकी स्थानीय भाषाओं को समझते हैं, जिससे उनको उनके भावों को समझने में आसानी होती है, उनकी उपलब्धता ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में न होना कहीं न कहीं एक बड़ी खामी को दर्शाता है।

पूर्व में भी हमने यह देखा है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ को जो बजटरी एलोकेशन्स हुए हैं, उसको लेकर हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है। हालांकि वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के बजट में 70 परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि काबिल-ए-तारीफ है, लेकिन इससे पहले के वर्षों में यह सामने आया है कि इस क्षेत्र में ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ और ट्राइबल शिक्षा को लेकर न्यूनतम स्तर पर इनवेस्टमेंट होने का कार्य हुआ है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा।

हमने यह भी देखा है कि जो आश्रम स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स और खराब होते जा रहे हैं। खासतौर से इन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, वे इन्हीं स्कूल्स में से निकलकर, आगे बढ़कर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन वहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड बद से बदतर होता चला जा रहा है। हाल ही में हमें देखने में आया था कि कुछ बच्चों को खास तौर से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं उचित नहीं थीं, बहुत ही अनुचित तरीके से उनको वहां पर रहना पड़ रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे ट्राइबल बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और वे आगे जाकर जब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचे तो उनके अंदर उच्च शिक्षा को ग्रहण करने की वे सारी की सारी तकनीकी व्यवस्थाएं हों, उनका दृष्टिकोण उस हिसाब से तैयार हो जाए। उसके लिए हमें ऐसे आश्रम स्कूल्स में, एकलव्य स्कूल्स में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है, जो हाल में हमें देखने को नहीं मिलती हैं।

वर्ष 2014 में हमने देखा था कि 793 बच्चों की इन आश्रम स्कूल्स में मृत्यु हो गई थी। हमें महाराष्ट्र का एक केस इस तरह का देखने को मिला था। इसी के साथ-साथ ऐसे स्कूल्स में हमें यह भी देखने को मिलता है कि किसी बिच्छू के काटने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है या किसी की सिर में दर्द से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे विद्यालयों की आज दयनीय स्थिति है।

मुझे इससे आशा और उम्मीद है कि आगे चलकर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इतना बड़ा प्रावधान कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो करीब-करीब 800 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे केसेज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। खासतौर पर शेड्यूल ट्राइब को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी ने निरंतर यह कहा है कि इनकी स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इनकी लोकल भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और ये जो दूर-दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, वहां आश्रम स्कूल्स और एकलव्य स्कूल्स में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनको सुदृढ करने की आवश्यकता है। जब तक बेसिक चीजें नहीं सुधरेंगी, तब तक ऐसी उच्च यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचकर वे अपने लेवल को हासिल नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m34 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Sir, at the inception, I do not have any qualms or dithering in according my unqualified support to this legislative document under the title, the Central Universities (Amendment) Bill, 2023.

Sir, today, it is a sheer providence and a coincidence that when the new Government in Telangana is going to be sworn in, today?s legislation will certainly add a new jewel to the crown of Telangana itself. In pursuance of the commitment that has been made by the predecessor Government, it was committed that one Central Tribal University in the State of Telangana will be established. In pursuance of that obligation, the Central Tribal University in the State of Telangana under the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 is going to be established. The fact is that all the Members across the spectrum are subscribing to the contents of this legislation.

<u>17.27 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, it is a fact that education is a key determinant to the growth and development of tribal population in our country. India is a multilingual and a multiracial country. We are boasting 574 tribal groups in our country. Across the world, out of the total tribal population, we share nine per cent of the population. But at the same time, the seamy side of all our development agenda is that there is still a conspicuous absence of our tribal pupils in higher education in our country. So, more participation of tribal students in higher education is an imperative need for the growth of the tribal society of our country. So, I would like to know from the hon. Minister what the current gross enrollment ratio of tribal pupils in our country is, which may suggest the growth of the tribal people along with their education.

Sir, in our educational system, already 7.5 per cent has been reserved for tribals. May I like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the number of vacant faculty posts in Central Universities disproportionately impacts candidates? eligibility under reservation quotas? 65.61 per cent of vacant posts are those which are reserved for the marginalized communities.

Out of that, the percentage of ST is 5.76. It clearly suggests that more priority should be given to enhance the participation of the tribal population not only in education but also in faculty so as to ensure their presence in each and every sector.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to another issue. According to the Minister of State for Education, who is also present here in the House, about 13,626 students from the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class communities have dropped out of the central universities, Indian Institutes of Technology and Indian Institutes of Management in the last five years. Again, I would like to be enlightened by the Minister concerned whether the Government has carried out any study to understand the reason behind such high dropout rates in these institutions.

It was stated that out of the total dropped out students in various institutions, around 4,596 OBC students, 2,424 Scheduled Caste students, and 2,622 Scheduled Tribe students dropped out from the central universities, while as many as 2,066 OBC students, 1,066 SC students and 408 ST students dropped out of the IITs, and 163 OBC students, 188 SC students and 91 ST students dropped out of the IIMs in the same period. So, certainly, I think it is a matter of grave concern to be noted.

It is even noted that elite institutions like the IIT, IIM have been hitting the headlines in the wake of alleged rampant casteism and other discriminatory practices faced by the students belonging to these communities in the campus. More than 33 students had died by suicide at various IIT and IIM campuses. In December, 2021, the Union Government had told Parliament that 122 students had died by suicide at the central higher educational institutions between 2014 and 2021. Out of the 122 students, 24 belonged to the Scheduled Caste community, three belonged to the Scheduled Tribes and 41 belonged to be OBCs.

In our country, since the Independence, a plethora of measures have been taken in order to bring, assimilate and include those isolated communities of our society, namely, the tribals, aborigines, primitive, *girijan* and *vanajati* to the mainstream of our society. In 1948, Dr. Radhakrishnan had prepared one education mission to that end. In the year 1968, the

Education Policy clearly demonstrated the endeavour of the Government to assimilate and to include those isolated societies in the mainstream. So, a plethora of measures have been taken by the successive Governments in the country but still they are lagging behind much to the concern of all of us.

So, I must suggest that they should be imparted more training and integrated services. Similarly, the girls of the tribal society should be guaranteed social security because you know that a section of tribal population in our country is still in the grip of various prejudices, superstitions, taboos, etc. etc.

सर, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उद्घाटन करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, तब उद्घाटन समारोह में एक ट्राइबल, आदिवासी लड़की, जिसका नाम बुधिनी मांझी था, उसने उनको माला पहनाई थी। उसी दिन से उस लड़की का समाज से बहिष्कार हो गया था। 80 साल गुजरने के बाद वह अपने गांव गई थी और उसके बाद उसका देहांत हो गया था।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर और अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। एजुकेशन के बारे में उनको थोड़ा और जागरुक करना है। इसके लिए पहल करना भी एक जरूरी मुद्दा है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्राइबल स्टूडेंस को पढ़ने के लिए सरकार पैसा जरूर देती है। श्री राजीव गांधी जी के ज़माने में फेलोशिप प्रोग्राम चालू हुआ था। A Central University for Tribals was also established in Amarkantak. हमारे मंत्री जी जिस स्टेट से आते हैं, वहां Kalinga Institute of Social Sciences है। इसे पूरी दुनिया में एक बड़ा प्रतिष्ठान माना जाता है। अत: काफी पहल हुई है, लेकिन फिर भी हमें और भी आगे जाना बाकी है।

सर, मैं इस सदन में, इस संदर्भ में बात रखते हुए आउट-माइग्रेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूं।

You will be astonished to note that students of Indian origin will be visible in 228 countries and dependent islands across the globe. About 17000 students are studying even in Bangladesh. Can you imagine that about 78 Indian students are studying in Afghanistan? Why? It is because the aspirational section of our society has been growing fast. The aspirations of the middle-class society do not match with the educational facilities of our country. So, there is a serious dearth of higher educational institutions in our country which has been prompting the exodus, I may say, outmigration of Indian talent. That means, brain drain has been continuing unabated. In order to defray their tuition fee and living expenses, those Indian students are spending Rs.6 lakh crores every year which is a mindboggling amount. Not only that, more than 40 lakh Indian students are studying abroad. So, what is the policy of this Government to bring back those talent into our country?

सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में हम एजुकेशन के ऊपर बड़ी चर्चा करते हैं, हम नॉलेज-बेस्ड सोसाइटी की बातें भी करते हैं। एक जमाना था, जब ब्रिटिश हुकूमत और बाहरी ताकतों ने, कोलोनियल फोर्सेज़ ने अपने एग्रेशन के चलते हमारे देश पर कब्जा किया था, लेकिन आज नॉलेज-बेस्ड सोसाइटी होने के नाते आज दुनिया को हमने अपने कब्जे में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आज हिन्दुस्तान के लोग पूरी दुनिया के कोने-कोने में छाए हुए हैं। चाहे वह अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी अन्य देश हो, हर जगह बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइजेशंस में बड़े-बड़े पदों पर, सबके माथे पर हमारे इंडियंस बैठे हुए हैं।

वे सब हमारे ऐसेट हैं। उन ऐसेट को हम वापस क्यों नहीं ला सकते हैं? इसमें हमारी क्या खामियाँ हैं? इन खामियों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

महोदय, मैं रविन्द्र नाथ टैगोर जी के देश से आता हूँ। स्वामी विवेकानन्द जी के देश से आता हूँ। हम जानते हैं कि रविन्द्र नाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, इन सारे विद्वानों ने हमारे देश की उच्च शिक्षा के लिए कितना प्रयास किया था। जो सोशल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया था। इसके लिए हमारे सौगत राय जी कह रहे थे कि शांति निकेतन बनी थी। बिल्कुल, हमारे देश के कोने-कोने में विद्वानों की पहचान है और इन विद्वानों के नाम से बहुत सारे प्रतिष्ठानों को हम जानते हैं। Swami Vivekananda had said that ?education is needed for building our character; education helps us strengthen our character; and it is our character that can cleave through the adamantine walls of all adversities.?

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैंने जो दो-तीन मुद्दे रखे हैं, मैं इनका जवाब माँगना चाहता हूँ और सेल्फी-सैवी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को यह भी नसीहत देते हैं कि सेल्फी-सैवी न होते हुए एजुकेशन-सैवी जो हमारे देश के नौजवान हैं, इनके लिए और ज्यादा सोचिए। इसमें हमारे देश की भलाई है। नमस्ते।

***m35 शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान):** महोदय, कल से केन्द्रीय विश्वविद्यालय 2023 (संशोधन) विधेयक आपने इस पवित्र गृह में अनुमोदन के पहले चर्चा के लिए अनुमति दी है। मेरे सहयोगी डॉ. सुभाष सरकार जी ने कल इसे आपकी अनुमति से प्रस्थापित किया था। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले इस सदन का सभी पक्षों की तरफ से, सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। 40 से ज्यादा सम्माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव इस विधेयक के बहाने सबके सामने रखे हैं। जिस मूल विषय के लिए आज चर्चा हो रही है, आन्ध्र प्रदेश बाइफरकेशन विधेयक में तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में, दो राज्यों में दो ट्राइबल विश्वविद्यालयों की प्रतिस्थिति थी, कमिटमेंट था, जिम्मेदारी थी। एक वर्ष 2018 में हो गया था। आज वह अवसर आया है। अधीर रंजन जी ने सही कहा कि जब तेलंगाना में एक नई सरकार बन रही है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि हमने कल मनायी है, ऐसे समय में तेलंगाना में एक नये जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने में इस सदन ने सर्वसम्मति से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसमें अमूमन सभी सर्वसम्मत होते हैं। पद्धति के बारे में किसी के थोड़े सुझाव और किसी की थोड़ी अलग पद्धति भी रहती है, लेकिन एंड-प्रोडक्ट के बारे में सब सहमत होते हैं।

***m36 माननीय अध्यक्ष :** अगर किसी को आलोचना ही करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं? अधीर रंजन जी को तो कई बार सकारात्मक नहीं, केवल आलोचना ही करनी है। क्या आप यह डिसाइड करके आते हो?

***m37 श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदय, मैंने आलोचना नहीं की है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रधानमंत्री जी समय-समय पर देश के नौजवानों को सम्बोधित करते हैं, उनका हौंसला बढ़ाते हैं। आप यह भी तो बोला कीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी**):** सर, उन्हें नेता को खुश करना होता है।? (व्यवधान)

***m38 श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं निश्चित रूप से चीजों को स्पष्ट करना उचित मानूंगा। हमारे प्रजातंत्र की यह ब्यूटी है कि कुछ विषयों में आज हम एकमत हो पा रहे हैं। आपके नेतृत्व में जो नया सदन बना

है, उसमें आज हम समाज के वंचित वर्ग के बारे में एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं। सम्मक्का-सारक्का तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण जनजाति महोत्सव है। सदियों से कई राज्यों की, न केवल तेलुगु भाषा भाषियों की, आंध्र और तेलंगाना, पड़ोस का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की कुछ जनजातियां इस सम्मक्का-सारक्का के उत्सव के साथ मेडारमा यात्रा, जिसका पूरा नाम सम्मक्का-सरक्का मेडारम यात्रा, मुलुगु जिले में है, संयोग से बहुत मशक्कत के बाद मित्रों ने यह विषय उठाया कि इतनी देरी क्यों हुई? देरी इसलिए हुई क्योंकि तेलंगाना सरकार इस यूनिवर्सिटी के लिए स्थान तय नहीं कर पा रही थी। बारंबार अनुरोध करने के बाद उन्होंने फाइनली स्थान दिया। कैबिनेट में पहले निर्णय हुआ और आज एक विधेयक आपके माध्यम से पारित होगा। सम्मक्का-सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को लगभग 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ बनाया जाएगा। आपके अनुमोदन के बाद इस प्रक्रिया को आगे ले जाया जाएगा। पहले मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी थी। बाद में इसी सरकार को, प्रधान मंत्री मोदी जी को सौभाग्य मिला और देश में दो ट्राइबल यूनिवर्सिटीज एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में बनाने का सौभाग्य मिला। उत्तर इसी में मिल जाता है, केवल कल्पना करने से या स्लोगन देने से शासन व्यवस्था नहीं चलती है, बल्कि करने से चलती है। मोदी जी सौभाग्यशाली हैं, वे करते ही हैं, इसीलिए उनके ऊपर जनता का विश्वास और भरोसा है और इसे करने का हमें आज सौभाग्य मिला।

अध्यक्ष जी, आज इस चर्चा में सभी ने चिंता व्यक्त की। मुझे मोह हो रहा था कि सभी का नाम लूं। हमारी बहन श्रीमती सुनीता मुद्गल से लेकर नेता विरोधी दल।? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सुनीता दुग्गल।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : जी हाँ, सुनीता दुग्गल। आप गार्डियन हो, आपका ही दायित्व है कान पकड़कर ठीक करना। लेकिन आप बार-बार सेल्फी के बारे में बोलने के लिए उठना नहीं, मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं आपका उतावलापन समझ सकता हूं। अधीर रंजन जी को आज कल खुश नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको ही खुश करना पड़ता है। दीदी को भी खुश करना पड़ता है और भतीजे को भी। आप चार बार उठे हैं, आप बैठिए, मैं आपको भी उत्तर दूंगा।? (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): आप पार्लियामेंट में आते हैं और उत्तर देते हैं कि मैंने राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है।? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैंने पार्लियामेंट में कहा नहीं है। अभी कहूंगा।? (व्यवधान) अभी भी कहूंगा।? (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: You have no authority to announce a CBI inquiry on the floor of the House.? (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं दादा का दर्द समझ रहा हूं। तीर कहीं लगा है तो आज कष्ट होना स्वाभाविक ही है। गरीबों का पैसा लूटोगे तो निश्चित रूप में कार्यवाही होगी ही होगी।? (व्यवधान) मैं सेल्फी के बारे में निश्चित उत्तर दूंगा। आप पहले दिन की बात कह रहे हैं। कभी आपत्ति लाओ तो उसके ऊपर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। आज देश की जनता को जानने का अधिकार है, विशेष करके बंगाल की जनता को अधिकार है कि ब्लैक एंड वाइट क्या हो रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी एक बार होना ही चाहिए कि बंगाल में क्या हो रहा है।? (व्यवधान) जोर-जोर से चिल्लाने से, थिएट्रिक करने से, ड्रामा करने से सत्य छुप नहीं जाता है। इस विषय को हम भी कभी-कभी सामने रखना चाहेंगे।

अध्यक्ष जी, देश आजादी की लड़ाई 19वीं सदी में भी लड़ा, 20वीं सदी में भी देश आजादी की एक लम्बी लड़ाई लड़ी और इसमें आधी सेंचुरी चली गई। 19वीं सदी के मध्य से देश के कई इलाकों में आंदोलन शुरू हुए। उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व के एक तबके ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब उस आजादी की लड़ाई के अग्रणी नेता रहे।

उसी समय, हमारे समाज जीवन में ऐसे कुछ मूर्धन्य व्यक्तित्व रहे, जिनमें स्वामी विवेकानन्द, योगीराज श्री अरविन्द, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, राधाकृष्णन, पंडित गोपबंधु दास जैसे लोगों का एक तबका रहा, जिन्हें यह ध्यान में था कि कुछ सालों के बाद देश आज़ाद हो जाएगा और जब आज़ाद हो जाएगा, तब देश की रचना कैसे होगी। अगर हम शिक्षा पर जोर नहीं देंगे, शिक्षा को भारतीयता के साथ नहीं जोड़ेंगे तो फिर कैसे होगा?

अध्यक्ष जी, वर्ष 1835 में अंग्रेज नीतिकार मैकाले ने एक मीटिंग बुलाई कि इस देश को ऐसे ही पराजित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1835 में अंग्रेजों ने यह तय किया कि अगर इस देश को लम्बे समय तक अर्थनीति की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से गुलाम बनाना है तो इस देश की जो मूल आत्मा शिक्षा है, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो यह संभव नहीं है। इसलिए पराधीनता की मानसिकता के आधार पर कोलोनियल रूल को लम्बे समय तक जारी रखने के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाई गयी। वे सारे महानुभाव, जिनका मैंने नाम लिया, सभी ने अपने-अपने तरीके से देश की अंतरात्मा को खड़ा करने के लिए काम किया।

महोदय, केरल के मुस्लिम लीग के माननीय सदस्य शायद अब्दुल्ला जी हैं। उनके भाषण की मैं प्रशंसा करूंगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था उसकी अंतरात्मा के साथ कैसे जुड़नी चाहिए, उन्होंने इसका आज उल्लेख किया है। सदन के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा की उस मौलिक आवश्यकता को भारतीयता के साथ जोड़ना और उसे आत्मनिर्भर बनाने जैसे इन सारे विषयों को रिकॉग्नाइज़ किया। इसके लिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों

के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभी का मर्म एक था कि हमें देश की गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। यह एक लम्बा प्रवास है। आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इस बिल के ऊपर सारे माननीय सदस्यों ने जिन-जिन विषयों का उल्लेख किया है, अगर मैं सारे विषयों को सारांश में देखता हूं तो उसमें तीन-चार विषयों पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता प्रकट की है, अपना कन्सर्न दिखाया है। आपकी अनुमति से मैं उसमें से एक-दो विषयों को मैं रखना चाहूंगा।

महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने ड्रॉप आउट के बारे में कहा है। सभी ने एस.सी./एस.टी./ओबीसी प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कहा है। कई सदस्यों ने डिस्क्रिमिनेशन को भी आज की चर्चा का विषय बनाया है। आपके माध्यम से मैं विनम्रता से सदन को दो-तीन विषयों से अवगत कराना चाहता हूं।? (व्यवधान)

सौगत दा, हम आपसे सीखते हैं। मैं बचपन से आपको जानता हूं। आप तथागत जी के भाई हैं। हम आपको आदर्श मानते हैं। मेरी और आपकी उम्र में पिता-पुत्र या छोटे भाई - बड़े भाई का अन्तर है। आपके सारे विषयों का उत्तर दूंगा। मैंने जब अख़बार पढ़ना सीखा, तब से मैं सुदीप दा का नाम पढ़ता आया हूं, लेकिन अगर आप लोग बालक जैसे स्वभाव के बन जाएंगे, तो कैसे होगा? मैं आपके सारे विषयों का बिल्कुल उत्तर दूंगा।? (व्यवधान)

दादा, मैं वही बात कह रहा हूं। जब मैं बालक था और उस समय जब मैं स्टेट्समैन पढ़ता था, उसमें मैं आपका नाम पढ़ता था। जो विषय आपने मुझे बाहर कहा, उसे मैं यहां नहीं कहूंगा। दादा, आप थोड़ा धीरज रखिए। हम आपका सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष जी, ड्रॉप-आउट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की। अधीर रंजन जी ने उसको कोट किया और लगभग सभी ने यह कोट किया कि पाँच सालों के अन्दर सेन्ट्रल इंस्टीट्यूशन्स से इतने लोग बाहर चले गए। यह स्टैटिस्टिक्स सही है, लेकिन यह अर्द्ध सत्य है। यह सत्य है, लेकिन इसके बेस का तो थोड़ा हिसाब लगाइए। जिस वर्ग से ये लोग आते हैं, इनकी सभी की जिन्दगी में, यहां भी कई माननीय सदस्य हैं, अगर उन्हें पढ़ाई पूरी करनी होती तो उन्हीं में से कुछ लोग नॉबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेते, लेकिन जैसी उनकी सामाजिक आवश्यकता है, जैसे घर में दिक्कत, परिवार में दिक्कत, खुद की आवश्यकता इत्यादि के कारण उनका पढ़ाई पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। किसी व्यक्ति को पहली बार में आई.आई.टी., भुवनेश्वर में एडमिशन मिल गया। उन्होंने वहां एडमिशन ले लिया। बाद में उन्हें फाइनली आई.एस.सी., बेंगलुरु में एडमिशन मिल गया। जब वह आई.आई.टी., भुवनेश्वर छोड़ कर आई.एस.सी., बेंगलुरु जाता है तो रिकॉर्ड में वह आई.आई.टी., भुवनेश्वर से ड्रॉप-आउट हो जाता है। उन्होंने पी.एच.डी. की है। पिछले दिनों हमने अध्यापकों की नियुक्ति की मुहिम चलायी। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पी.एच.डी. होना अनिवार्य है, जो पहले से ही था।

हमने देखा कि इस कारण से एससी एवं एसटी वर्ग के लोग अच्छे तरीके से नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमने उस अनिवार्यता को हटा कर पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, तो जो पीएचडी कर रहे थे, वे छोड़ कर फिर जॉइन कर गए। इसलिए ऐसे सारे लोगों का ड्रॉपआउट तो दिखेगा न? 5 सालों का जो नंबर आपने दिखाया है, यह सत्य नहीं है कि ये लोग पढ़ाई छोड़ कर चले गए। जिसको आदरणीय निशिकांत जी ने अध्ययन कर के आपके सामने रखा है कि ये दूसरे ऑप्शंस के लिए, दूसरी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या परिवार के लिए और कुछ कष्ट है, उस कष्ट को मैं स्वीकार करता हूँ, उस कष्ट के लिए वे बाहर गए। अगर अभी मैं एनरोलमेंट की बात कहूँ, कई मित्रों ने उसको पूछा है कि एनरोलमेंट का क्या है। मेरे मित्र सप्तगिरी जी ने अमरकंटक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बारे में कहा और कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ट्राइबल विद्यार्थियों के बारे में कहा। मैं पहले दो आंकड़ों का उत्तर देता हूँ। मेरे मित्र सप्तगिरी जी, शायद आपके तथ्य पर्याप्त नहीं हैं, सही नहीं हैं। मेरे पास पिछले 5 सालों के जो तथ्य हैं, उनमें कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी भी 8 पर्सेंट से नीचे ट्राइबल छात्र उस संस्थान में नहीं रहे हैं। सभी समय में 7.9, 11.15, 9.44, 9.34 पर्सेंट रहे हैं, संविधान की व्यवस्था के हिसाब से एसटी छात्रों का रिज़र्वेशन 7.5 पर्सेंट होना चाहिए। लेकिन कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिज़र्वेशन कैटेगरी से ज्यादा विद्यार्थी आज भी पढ़ते हैं। अगर मैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक की बात करूं तो वहां किसी भी वर्ष में 13, 14 या 15 पर्सेंट से कम ट्राइबल छात्र नहीं पढ़ते हैं। यह जो एक धारणा है, आज भी कई सदस्यों ने चर्चा की है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी, तो वहां केवल ट्राइबल छात्र पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ट्राइबल इलाके में होगी, ट्राइबल विषयों पर चर्चा होगी, ट्राइबल चैलेंजेस के बारे में चर्चा होगी और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जितना ट्राइबल रिज़र्वेशन है, उतने विद्याथी पढ़ेंगे। आज तो उस संस्थान में उससे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह तथ्य शायद सप्तगिरी के पास पर्याप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं आज 2 बेस लाइन पर आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2014 में देश की सेवा करने का अवसर मिला, तब देश में, एबसॉल्यूट नंबर में, उच्च शिक्षा में, 3 करोड़ 42 लाख विद्यार्थी थे। यह जीईआर तब 23 पर्सेंट होता था। उस आयु के बच्चों के अंदर यह 23 पर्सेंट होता था। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो 23 पर्सेंट होता था। इसी साल, यानि वर्ष 2021-22 में ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे के आंकड़े आए हैं, जो कि मेरे हाथ में हैं। वर्ष 2021-22 के सर्वे के हिसाब से यह बढ़ कर 28 पर्सेंट हुआ है। 23 से 28 पर्सेंट हुआ है और एबसॉल्यूट नंबर में 4 करोड़ 32 लाख हुआ है। अगर इसकी ग्रोथ को मैं आपके सामने विनम्रता के साथ रखूंगा तो चिंता का कोई कारण नहीं है। मैं फिर एससी, एसटी और ओबीसी के आंकड़ों पर आऊंगा। आज भारत में नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। नए क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस खुल रहे हैं। उसके कारण नए-नए कोर्सेज़ खुल रहे हैं। पहले हमारे यहां एआई में अण्डर ग्रेजुएट कोर्सेज़

नहीं थे। पहले हमारे मेडिकल इंस्टिट्यूट्स और इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूट्स मिल कर जॉइंट कोलैबोरेटिव कोर्स नहीं चलाते थे। आज भारत की कई सारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ द्वारा इस प्रकार के नए कोलैबोरेटिव इंस्टिट्यूशन चलाने के कारण देश का विद्यार्थी देश में पढ़ता है। इसके कारण आज देश में लगभग 26.5 पर्सेंट ग्रोथ, 2014 से 2021-22 तक हई है। अभी 2023 का हिसाब आने वाला है, तब थोड़ा और बढ़ेगा। यह विशेषकर महिलाओं में हुआ है। आदरणीय सुप्रीया ताई ने महिलाओं के बारे में अच्छी चिंता की है। मैं उस चिंता को स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन मैं वर्ष 2014 और 2021-22 का कम्पैरिज़न देता हूँ। वर्ष 2014 में जितनी महिलाएं पढ़ती थीं, छात्राएं पढ़ती थीं, उनकी तुलना में आज 31.6 पर्सेंट ज्यादा पढ़ रही हैं। यही सरकार की उपलब्धि है। आज एसटी की चर्चा हो रही है। मैं एसटी की बात कर रहा हूँ। एसटी की टोटल ग्रोथ में 65.2 पर्सेंट ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा ग्रोथ एसटी की हुई है। ? (व्यवधान)

18.00 hrs

***m39 माननीय अध्यक्ष:** अगर सदन की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी के जवाब और विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

***m40 श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** अध्यक्ष जी, अगर मैं एसटी गर्ल्स स्टूडेंट्स का कम्पैरिजन वर्ष 2014-15 और वर्ष 2021-22 के बीच में करूंगा तो इसमें 80 परसेंट ग्रोथ हुई है। एससी की टोटल ग्रोथ 43.8 परसेंट हुई है। उसमें वूमेन की ग्रोथ लगभग 51 परसेंट हुई है। ओबीसी की ग्रोथ 45 परसेंट हुई है। उसमें वूमेन की ग्रोथ 49.3 परसेंट हुई है। देश में ओवरऑल जितने विद्यार्थी पीएचडी कर रहे थे, वर्ष 2014-15 में 1,17,301 पीएचडी रजिस्ट्रेशन था। इस देश के वैज्ञानिकों के आक्रोश के कारण, आज उसकी संख्या 2,13,000 हो चुकी है। इसमें 81 परसेंट की ग्रोथ हुई है। महिला पीएचडी के बारे में हमारे सुदीप दा और सौगत दा को चिंता हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी की सेल्फी प्वाइंट क्यों बना रहे हैं। इसे हम इसीलिए बना रहे हैं कि जब चंद्रयान 3 की सक्सेस हुई, तब हमारे प्रधानमंत्री जी बेंगलुरू पहुंच कर, वहां जो महिला वैज्ञानिक काम कर रही थी, सबसे ज्यादा प्रशंसा उन्हीं की की। क्या यह गौरव का विषय नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री किसी दल के होते हैं, क्या वह किसी वर्ग के होते हैं? हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे स्कूलों और ऑफिसेज़ में राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और फादर ऑफ दी नेशन महात्मा गांधी जी के फोटो लगे रहते हैं। आज हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले, विश्व में भारत को अव्वल नंबर तक पहुंचाने वाले और विकसित भारत बनाने की आह्वान देने वाले नेता का अगर हम गौरव से सेल्फी प्वाइंट लगाते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? यह प्रजातंत्र है। आप भी गौरव कीजिए। आपको नहीं उठाना है तो नहीं उठाइए। हमारे बच्चे तो उठा ही रहे हैं। यह कोई कंप्लसरी नहीं है। हमारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

महोदय, आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के बाद महिला पीएचडी की 106 परसेंट ग्रोथ हुई है। सुप्रिया ताई, वर्ष 2014 में बागडोर आपके हाथ में थी, आपके हाथ में मौका था। वहां बैठे हुए मित्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी देश और राज्यों के शासन के दायित्व में थे, आपको किसी ने मना नहीं किया था। अगर आज हमें सेवा का मौका मिला है तो हमने फोकस किया है। पीएचडी करने वाली महिलाओं की संख्या 106 परसेंट बढ़ी है।

अध्यक्ष जी, अभी शिक्षक नियुक्ति के बारे में चर्चा हो रही थी। आज मैं इस पवित्र गृह में एक तथ्य ऑन रिकॉर्ड रखना चाहूंगा। जब मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में आया, तो डीएमके के कुछ मित्र, तमिलनाडु के कुछ मित्र, आज वे यहां नहीं हैं, वे मुझसे मिलने के लिए आएं। उन्होंने कहा कि साहब, हमारे देश की आईआईटीज़, एनआईटीज़ और सेंट्रल इंस्टीटयूशंस में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। मैं विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक न्याय का समर्थक हूं, उसका प्रैक्टिशनर हूं, विश्वासी हूं। हम बचपन से ही बाबा साहब अंबेडकर के लिए 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को मनाते आए हैं। जब मैंने विभाग के अधिकारी मित्रों से चर्चा की, तब हमें पता चला, मैंने एक रिसर्च स्टूडेंट के रूप में पूरा असेसमेंट किया, जिनके आँखों में क्रोकडाइल टियर्स हैं, जो घड़ियाली आँसू बहाते हैं, इस सदन में लंबे-लंबे भाषण देते हैं, फिर मैं कहूंगा, जिनके हाथ में दशकों तक शासन रहा, उन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीटयूशन में एससी, एसटी टीचर अप्वाइंटमेंट में रिजर्वेशन के बारे में क्या कानूनी व्यवस्था की थी? सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करने वाले लोगों ने क्या किया था? जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वर्ष् 2019 में पहली बार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एक्ट आया, जिसको मिशन मोड पर चलाने के लिए लाया गया है। उसमें एक कानून लाया गया।

जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें स्टूडेंट टीचर रेश्यो में जितने टीचर्स रहेंगे और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है और ओबीसी के लिए कितना है, उतने ही टीचर्स बिना कम्प्रोमाइज के अपॉइंटमेंट होंगे। वर्ष 2019 में पहली बार यह कानून आया, नरेन्द्र मोदी जी ने इसे किया। पहले आपके हाथ में दायित्व था। आज आप बहुत प्रश्न उठाते हैं कि क्यों खाली है? लेगासी इश्यू है। आज हमको मौका मिला है उस पवित्र काम को करने का, पुण्य करने का। मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं। 28 अक्टूबर, 2023 को, लेटेस्ट, देश में सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स में जो वैकेंसीज़ हैं, उसका स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखता हूं। लोग रिटायर होते हैं, नई नियुक्तियां होती हैं, इसलिए पद का यह खालीपन बराबर बना रहता है। अगर मैं 28 अक्टूबर, 2023 का कोट करूं तो 18,019 पोस्ट्स एकैडेमिक्स में खाली थीं। पिछले दिनों में, अक्टूबर से 7 दिसम्बर तक का मैं हिसाब दे रहा हूं। प्रधान मंत्री जी हर एक महीने में रोजगार मेला करके नियुक्ति देते हैं। 11,272 नियुक्तियां पिछले दो महीने में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में पूरी हुई हैं। उसमें एससी 1402, लगभग 12 पर्सेंट, एसटी 572, लगभग 5 पर्सेंट, ओबीसी 2,321, लगभग 21 पर्सेंट नियुक्तियां अभी पिछले दो महीने में हुई हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में 6,747 में 854 एससी, 307 एसटी, 1,441 ओबीसी नियुक्त हुए। मैं यह दो महीने की स्टैटिस्टिक्स दे रहा

हूं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स शामिल हैं। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, टीचिंग, नॉन-टीचिंग, आज एक मिशन मोड पर इसको भरने का हम काम कर रहे हैं। इसका एक्ट लाये और भर भी रहे हैं। आज हमारे समय में ड्रॉप आउट की संख्या, स्टैटिस्टिक्स मैंने दिया। आज एनरॉलमेंट में, जीआर में हमारी बढ़ोत्तरी क्या हो रही है, मैंने आपके सामने उसका एक तथ्य रखा।

महोदय, निवेश के बारे में चर्चा हुई कि उच्च शिक्षा संस्थान में ज्यादा निवेश होना चाहिए। ?(व्यवधान) दादा को और एक बार मैं थोड़ा उस ट्राइबल जीआर के बारे में बता दूं। जब वर्ष 2014-15 में आपका दायित्व था, उस समय में ट्राइबल 16 लाख 41 हजार विद्यार्थी थे, उसमें 65 पर्सेंट ग्रोथ हुई है। अगर 3 करोड़ 42 लाख में से 16 लाख की गिनती करूं, तो यह लगभग साढ़े 4, 5 पर्सेंट होता है और आज 4 करोड़ 32 लाख में से 27 लाख 10 हजार विद्यार्थी हो चुके हैं। इसमें 65 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है। जो कांस्टीट्यूशनल मैनडेट है, 7.5 पर्सेंट, नियरिंग दैट, पिछले नौ सालों की सरकार में यह ट्राइबल जीआर की उपलब्धि है।

अध्यक्ष जी, निवेश के बारे में, एक्सपेंडीचर इन एजुकेशन कहा गया। कई मित्रों ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में चार, पांच, छ: पर्सेंट होता है। भारत में जब हमारा दायित्व वर्ष 2013-14 में आया, तब एजुकेशन की स्पेंडिंग जीडीपी की 3.84 पर्सेंट थी, जो आज बढ़कर 4.64 पर्सेंट हुई है, लगभग 1 पर्सेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट। पिछले दिनों में, 2013-14 में जिनके हाथों में शासन था, उनसे आज हम 30-35 हजार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पिछले दिनों में, हमारे देश में 7 नये आईआईटीज़ बने हैं।

सात नये आईआईएम बने हैं, दो नए आईआईएसईआर बने हैं, 16 ट्रिपल आईटी बने हैं, कोटा में भी एक ट्रिपल आईटी बना है। एक नया एनआईटी बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 7 और इसको मिलाकर 8 बने हैं। 40 से ज्यादा नयी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। कुल मिलाकर डेढ़ सौ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स हैं, जिसमें पिछले 8 सालों में 40 हमने ही जोड़े हैं। इस काल खंड में ही जोड़े हैं, यह इस सरकार की उच्च शिक्षा में खर्च बढ़ाने के बारे में प्रतिबद्धता है।

ट्राइबल कमिटमेंट के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया। मैं चार-पांच विषयों के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। अटल जी ने देश में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया। प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पहली बार मनायी। पहले भी बिरसा मुंडा थे। उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई नही की थी, बाकी लोगों को भी याद करने की जरूरत थी। हमें सौभाग्य मिला, हमने उनको सम्मान दिया। आप कुछ भी कहें, इन दिनों मुझे सौभाग्य मिला।

मैं ओडिशा से आता हूं, लेकिन कभी आदरणीय राष्ट्रपति जी के गांव में नहीं गया था। वह मेरे गांव आते थे तो मैं उनके साथ में रहता था। झारखंड और ओडिशा के बार्डर पर अत्यंत ट्राइबल कन्सट्रेंट इलाका है। मैंने आंखों की चमक देखी है। पहली बार देश में अपनी जिन्दगी को एकदम दरिद्रता, bottom of the pyramid से उठ कर आने वाली महिला इसी काल खंड में देश की राष्ट्रपति बनी हैं। कोई कुछ भी कहे, महिला और जनजाति, हमें प्रजातंत्र में महिमामंडन करने का सौभाग्य मिला। यह इसी काल खंड में हुया है।

इसमें कोई वोट का संपर्क नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में 24 लाख 70 हजार पीवीटीजी, आदिम जनजाति के लोग हैं, लोग कहते हैं कि सेल्फी क्यों उठाते हैं, इसीलिए उठाते हैं। आपको सत्ता के सात दशक मिले, लेकिन आपने गौरव नहीं किया। मेरे नेता ने याद करके बिना वोट की चिंता रखते हुए 24 हजार करोड़ रुपये उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ के लिए खर्च किए हैं। यह जनजाति विकास के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

प्रधानमंत्री जन मन योजना आज शुरू हुई है। 700 से ज्यादा एक्लव्य विद्यालय ट्राइबल कन्सन्ट्रेट ब्लॉक में बन रहे हैं। इसमें 28 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, एक स्कूल बनाने में लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च होगा। यह इस सरकार की उपलब्धि है। मुझे सौभाग्य मिला, मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ विजयनगरम गया, शायद यह नया जिला बना है। शायद इस सदन ने अल्लूरी सीताराम राजू का नाम नहीं सुना होगा। हम सौभाग्यशाली लोग हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश इलाके के अल्लूरी सीताराम राजू वीर पुरुष थे, आदिवासी थे, देश के गौरव के लिए लड़े थे। आज हम उन्हीं के जिले में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में बना रहे हैं।

हमारी प्रतिबद्धता लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। लोगों के लिए करने के लिए है। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे आए हैं। आज सभी ने शिक्षा के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हमें विरासत में मैकाले शिक्षा पद्धति मिला था, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की।

सौगत दा, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे राज्य के महापुरुष विधु भूषण दास जी का नाम लिया। एक ओडिया होने के नाते मैं कृतज्ञ हूं, आपने कम से कम याद तो किया। उन जैसे शिक्षाविदों के कारण देश में एक वैकल्पिक शिक्षा बननी चाहिए, भारतीयता के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा बननी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में नयी शिक्षा नीति एक दार्शनिक तत्व हमारे सामने है. It is a philosophical document for 21st century to create global citizens, जिसमें अमृत काल में आने वाले 25 सालों में देश के विद्यार्थी, देश के नौजवानों की रचना कैसी होगी, उनकी मन:स्थिति कैसी होगी, विकसित भारत बनाना है तो शिक्षा ही कुंजी है। शिक्षा ही टर्न एराउंड करेगी कि क्या-क्या शिक्षा होनी चाहिए। आज सभी लोग उसी में सहमति दिखा रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाना है।

मैं राष्ट्रीय शिक्षा के दो-तीन फीचर्स के बारे में कहूंगा। कई लोगों ने आदिवासी भाषा के बारे में कहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का है जिन्होंने कहा कि भारत की सभी स्थानीय भाषाएं, सभी मातृ भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, चाहे वह ओलचिकी हो, मुंदारी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मलयाली हो, पंजाबी हो या असमिया हो, सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। लोग भाषा के आधार पर समाज को बांटने में लगे थे, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भाषा से जोड़ने का काम किया।

मैं अपने मित्र सप्तगिरी जी के जिले कोरापुट में गया था, वहां ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। वहां ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्या काम करती है? वहां दो लोकल लैंग्वेजेज में बोला जाता है, एक को कुई भाषा कहते है और दूसरे को देशीय भाषा कहते हैं। सप्तगिरी जी, आप थोड़ी प्रशंसा तो कर देते कि हमने दो प्राइमर निकाले हैं, आप तो पढ़े-लिखे हैं, आपको तो मालूम है, हम आपके जिले में 1 अप्रैल में गए थे, उत्कल दिवस के दिन गए थे। वहां जो स्थानीय भाषा बच्चे घर में सुनकर आते हैं, उसी को उड़िया भाषा के साथ लिंक करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए प्राइमर भाषा बनाई है। भारत सरकार भारत की सभी स्थानीय भाषाओं को पढ़ाने का स्टाइल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। टेक्नोलॉजी में यह संभव है।, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि संभवत: आठवीं तक भारतीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है, भारत की सभी 22 शैड्यूल्ड लैंग्वेज़ेज को भारत सरकार ने, भारत की संविधान व्यवस्था ने शैड्यूल्ड किया है और सारी शैड्यूल्ड लैंग्वेज़ेज में धीरे-धीरे सीबीएसई पाठ्य पुस्तक और टीचिंग लर्निंग मैटीरियल बना देगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंश है। आज भारत सरकार काशी-तमिल संगमम आयोजित कर रही है, दूसरी बार कर रही है। काशी और तमिल संस्कृति, दोनों का अभिन्न संपर्क है और आज उस भाषा को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है।

आज की शिक्षा नीति का मकसद सिर्फ जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। अब एक फंडामेंटल एप्रोच बदली है। हमें स्किल्ड मैन पावर बनानी है। ड्रोन आ गया है, ब्लॉक चेन आ गई है, टेक्नोलॉजी के नए आयाम आ गए हैं। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी एकांगी रूप में पढ़ाया जाता था, अब इसे इकट्ठा पढ़ाना पड़ेगा और मल्टीडिसीप्लेनरी करना पड़ेगा। हम सारी व्यवस्था का आज की राष्ट्रीय नीति में विज़न कर रहे हैं। अब हमारी प्रॉयारिटी का विषय एन्टरप्रियोनरशिप है। कई मित्रों ने रैंकिंग के बारे में कहा है। महाराष्ट्र, औरंगाबाद के आदरणीय सदस्य ने रैंकिंग के बारे में कहा। आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन यह रैंकिंग रातों रात नहीं होगी। अभी-अभी क्यूएस रैंकिंग आई जिसमें पहली बार भारत के इंस्टीट्यूशन्स तेजी से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस, बेंगलुरू रिसर्च में दुनिया के पांच इंस्टीट्यूशन्स में से एक बन चुका है। यह आज भारत की वैज्ञानिक शक्ति की उपलब्धि है। हम कितने दिन बाहर वालों के सर्टिफिकेट से चलेंगे। वर्ष 2014 के उपरांत हमने एनआईआरएफ रैंकिंग व्यवस्था भारत में शुरू की है। नैक धीरे-धीरे हम सभी इंस्टीट्यूशन्स में कम्पलसरी करने जा रहे हैं, सभी को एक्रेडिटेशन करना पड़ेगा। कई सदस्यों ने चिंता प्रकट की है कि कमर्शियलाइजेशन नहीं होना

चाहिए। यह बात सही है, विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि नैक एक्रेडिटेशन में मैं जिस इंस्टीट्यूशन का फार्म भर रहा हूं, उसका स्तर क्या है? अब हम इसे करने वाले हैं। इसमें तेजी से नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन का दायरा बढ़ाया है, एनबीए का दायरा बढ़ाया है, यह आज हमारी प्रेक्टिस बन चुकी है। कई सदस्यों ने चिंता प्रकट की कि बच्चे बाहर चले जाएंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी तो फीस बढ़ जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पवित्र सदन को बताना चाहता हूं और आपको सुनकर गर्व होगा कि अब माननीय प्रधान मंत्री जी को विश्व के देशों का नेतृत्व करने वाले फोन करते हैं कि हमें आईआईटी दीजिए। अब भारत की प्रेस्टीजियस आईआईटी, दिल्ली आबूधाबी में अपना कैम्पस खोल रही है और थोड़े दिनों में वहां पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। दादा, यह उनके खर्चे पर है, हम एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, अफ्रीका महादेशों को ध्यान में रखते हुए तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास, अपना कैम्पस खोल चुका है।? (व्यवधान) दादा ठीक है, मैं मान गया। मैं आपसे क्यों उलझूं, क्यों तर्क करूं? आप स्वयं जाकर आए हैं, मैं क्यों उलझूं? अध्यक्ष जी, रूडी जी यहां हैं और उधर से अधीर दा ने भी स्वीकृति दी कि हमारे राज्य में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आज देश के लिए गौरव ला रहा है। वहां आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक अच्छा मॉडल खड़ा किया है। भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विदेश जा रही हैं। आज भारत की यूनिवर्सिटीज में ?स्टडी इन इंडिया? भारत में आकर पढ़िए, ऐसी व्यवस्था में विश्वभर के अनेक विद्यार्थी भारत आने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें हम पढ़ाने के लिए भारत लाएंगे। वे भारत आएंगे, पढ़ेंगे तो भारतीयता को लेकर लौटेंगे। आज भारत की शिक्षा नीति उस दिशा में काम कर रही है। ? (व्यवधान) दादा, आप बैठ जाइए। जब आईआईटी आबूधाबी में खोलने का प्लान किया तो वहां के मंत्री कुछ बच्चों को लेकर आईआईटी, दिल्ली लेकर आईं। बूट कैंप, समर कैंप लगाने के लिए दिल्ली आईं। मैं भी उनका स्वागत करने के लिए और मिलने के लिए गया। वह मंत्री अपने बच्चों को समझा रही थीं ?Do you know what this institution is? This is IIT. If you want to become a CEO, if you want to become ?Sundar Pichai?, then you have to study here.? देखिए दादा, दुनिया बदल चुकी है। जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, वे देश का ही काम कर रहे हैं। आज अजय बांगा वर्ल्ड बैंक में अध्यक्ष हैं। जब जी-20 हुआ था, तब प्रधान मंत्री जी ने उन्हें बुलाया था। वे कहते हैं कि मैं बाहर नहीं पढ़ा हूं। मैं देसी हूं, मैं मेड इन इंडिया हूं। मैं बाहर जाकर विश्व बैंक का अध्यक्ष बन चुका हूं। भारतीय मूल का व्यक्ति आज यूके के प्रधान मंत्री बन चुके हैं। आज पुराना जमाना चला गया, आप थोड़ा आगे बढ़ें।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यहां से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग बाहर चले जाते हैं।? (व्यवधान) वे अफगानिस्तान चले जाते हैं, अफ्रीका चले जाते हैं। यह चिंता का विषय है।? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दादा, यह चिंता का विषय है, आज इसीलिए भारत ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बाहर के क्वालिटेटिव विश्वविद्यालयों को भारत में आकर अपना कैम्पस खोलने की पहली बार हम अनुमति देने वाले हैं, यह कानून यूजीसी की ओर से हो चुका है। दो फॉरेन यूनिवर्सिटीज ? वॉलोंगोंग और डिकेन गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैम्पस अगले शिक्षा वर्ष से बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे और कम खर्च में ग्लोबल स्टैंडर्ड की स्टडी यहां भी हो सकती है। धीरे-धीरे दुनिया बदल रही है और हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मैं एक-दो विषयों का थोड़ी विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा। सभी लोगों ने अच्छी चर्चा की है और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लोगों ने अपने मत रखे। मैं एक नागरिक के नाते, संयोग से शिक्षा विभाग के मंत्री के नाते जब इस विषय का उत्तर देता हूं, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं कि मेरा दिल भर आता है और मेरे पास उत्तर नहीं होता है कि कभी एक सभ्य समाज में हमारी आईआईटी, आईआईएम या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लड़के को आज के समाज में यदि किसी कारण से अपने अमूल्य जीवन से हारना पड़ता है, तो इससे बड़ी दुखद घटना किसी के लिए नहीं हो सकती है। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं।

अगर दुनिया हमें उंगली दिखाए तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं, एज ए नागरिक और एज ए शिक्षा मंत्री। मैंने पहले भी कहा है और आज इस पवित्र गृह में भी इस बात को कहता हूं कि यह समाज का दायित्व है। हम सभी को इस विषय से जूझना पड़ेगा। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। अगर रोहित वेमुला की बात की जाएगी, दादा अगर आप विश्व भारती की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यादवपुर यूनिवर्सिटी भी है। मैंने बंगाल सरकार की विवशता को भी देखा है। सुदीप दा और सौगत दा, दोनों के पड़ोस में यादवपुर यूनिवर्सिटी है। क्या आप और हम इससे सहमत हो सकते हैं? क्या यादवपुर में जो हुआ, वह अच्छा हुआ? क्या उसमें हम राजनीति करेंगे? मैं तो नहीं करने वाला हूं। हमें सारे विषय को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी कैंपस में, सरकार किसी की भी हो, अगर किसी बच्चे का जीवन जाता है तो हम सभ्य समाज के लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, मैं जिम्मेवार हूं। मैं मुंह छुपाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे नेता का यह संस्कार नहीं है। हम उस समस्या को जड़ तक जाकर समझने वाले लोग हैं। इसीलिए, सारी रचना बनाई गई है। यह कोशिश है। शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। आज कई प्रकार की जाति की रचना की जाती है। आज मैंने शिक्षा का एक स्टैस्टिक्स दिया है, जिसमें हमारे कार्यकाल में एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित वर्गों के लोगों की पढ़ाई का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आज देश में चार ही जातियां हैं। गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, महिला एक जाति है और युवा एक जाति है। विकसित भारत के लिए चार जातियों की शिक्षा, आज की सम्मक्का, सरक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम निवेदन लेकर आए हैं। यह पवित्र गृह इसका अनुमोदन करेगा। हम भारत को वर्ष 2040 तक विश्व की एक ताकतवर देश बनाएंगे। इसी संकल्पना के साथ मैं सभी का समर्थन चाहता हूं। धन्यवाद।

***m41 माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

?कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Insertion of new section 3G

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 मूव करना चाहते हैं?

***m42 DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ):** Sir, I beg to move:

?Page 1, line 8,-

f*or* ?a body corporate?

substitute ?run by the Central Government?. (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 मूव करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment no. 2 to clause 2.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3, 4 एवं 5 मूव करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN: Sir, I beg to move:

?Page 1, line 11,-

after ?avenues of?

insert ?free?. (3)

?Page 1, line 11,-

after ?higher education?

insert ?and scholarship?. (4)

?Page 1, line 12,-

for ?primarily?

substitute ?only?. (5)

***m43 माननीय अध्यक्ष :** अब मैं डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3, 4 एवं 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुमलता अम्बरीश - उपस्थित नहीं।

श्री एम. के. राघवन - उपस्थित नहीं।

श्री अब्दुल खालेक - उपस्थित नहीं।

श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 13 मूव करना चाहते हैं?

***m44 श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, मुर्शिदाबाद जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पैसा दिया कीजिए। वे मर रहे हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुर्शिदाबाद जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बना है। आप उनको पैसा दिया कीजिए। हम कुछ नहीं चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप संशोधन मूव कर रहें हैं या नहीं कर रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी : नहीं सर, ठीक है। हम बस यही मांग कर रहे हैं।

***m45 माननीय अध्यक्ष :** एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 14 मूव करना चाहते हैं?

***m46 ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** Sir, I beg to move:

Page 1, after line12,-

insert ?3H. There shall be established a Tribal University, which shall be a body corporate, be known as the Idukki Central Tribal University, having its territorial jurisdiction extending to the whole of the State of Kerala, as specified in the

First Schedule to this Act, to provide avenues of higher education and research facilities primarily for the tribal population of India.?.

(14)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री हैबी ईडन ? उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Amendment of First Schedule

माननीय अध्यक्ष : श्री अब्दुल खालेक ? उपस्थित नहीं।

श्रीमती सुमलता अम्बरीश ? उपस्थित नहीं।

श्री एम. के. राघवन ? उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

***m47 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, I am moving the amendment. This is an amendment to establish a Central Marine University in any coastal city.

I beg to move:

Page 2, *after* line 5,-

insert ?18. Kerala Central Marine University, Kollam Whole of the State of Kerala.?. (12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

***m48 ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** Sir, I beg to move:

Page 2, *after* line 2,-

insert ?12a. Kerala Idukki Central Tribal University Whole of the State of Kerala.?. (15)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

***m49 श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदय, नहीं। मेरी वही मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुर्शिदाबाद कैंपस को पैसा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री हैबी ईडन ? उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

***m50 श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.33 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Friday, December 08, 2023/Agrahayana 17, 1945 (Saka).

-

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

---

* Treated as laid on the Table.

* Not recorded as ordered by the Chair.